वर्ष 12 • अंक 259 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 18 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

चीनी निर्यात 50 लाख टन के रिकॉर्ड पर पहुंचने के आसार

निखिल चोपड़ा पृष्ठ 2

आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगी सिप्ला

डॉलर रु. 71.00 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.20 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37959 ▲ 77 रुपये | सेंसेक्स 41352.20 ▲ 413.50 | निफ्टी 12165.00 ▲ 111.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12187.20 ▲ 22.20 | ब्रेंट क्रूड 67.30 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लिए शुल्क एक साल बढ़ा

दूरसंचार नियामक ट्राई ने किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर 6 पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा। पहले यह शुल्क 14 पैसे प्रति मिनट था लेकिन 1 अक्टूबर, 2017 को इसे घटाकर 6 प्रति मिनट किया गया था। 1 जनवरी, 2020 से इस शुल्क को समाप्त किया जाना था। नियामक ने कहा कि अब वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल पर 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क 1 जनवरी, 2021 से समाप्त होगा।

जेट एयरवेज में दो विदेशी कंपनियों की रुचि

बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के समाधान पेशेवर ने मंगलवार को एनसीएलटी को सूचित किया कि इस विमानन कंपनी के पुनरुद्धार में दो अन्य विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब तक जेट एयरवेज के लिए एकमात्र बोलीदाता दक्षिण अमेरिका की विमानन कंपनी सिनर्जी ग्रुप थी। समाधान पेशेवर ने नैशनल कंपनी लॉ पंचाट (एनसीएलटी) को यह भी बताया है कि उन्हें सिनर्जी ग्रुप से कारोबारी योजना का मसौदा करीब एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ। जेट एयरवेज के लिए समाधान योजना जमा कराने की अंतिम समय-सीमा 16 दिसंबर थी। पृष्ठ 2

उच्चतम न्यायालय का जांच समिति बनाने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शन की घटनाओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचियों से कहा कि वे राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में जाएं जो इस तरह की जांच गठित कर सकते हैं। पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य का संज्ञान लिया कि याचियों के आरोपों के प्रत्येक तथ्य को केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने गलत बताया। पृष्ठ 12

मार्च तिमाही में शुरू होगा 5जी परीक्षण

5जी का परीक्षण मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू हो सकता है। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पूछने पर कि क्या सरकार ने हुआवे की भागीदारी के बारे में कोई फैसला लिया है, अधिकारी ने कहा कि 5जी के परीक्षण के लिए अब तक 12 आवेदन मिले हैं लेकिन सरकार ने अब तक न तो किसी आवेदन को स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 5जी के किसी भी प्रस्ताव में दो चीजों पर जोर होना चाहिए। पहला नई प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता।

देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है लेकिन सेना ने विरोध किया है।

त्यापार गोष्ठी

सहकारी बैंकों की व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या अग्रिम कर संग्रह में नरमी से कर संग्रह लक्ष्य से चूकेगी सरकार

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या जीएसटी क्षतिपूर्ति की किस्त मिलने से दूर होगी राज्यों की नाराजगी?	हां	71.43%
	नहीं	28.57%

अग्रिम कर संग्रह की धीमी रफ्तार

कंपनियों से मिलने वाले अग्रिम कर संग्रह में 5 फीसदी से ज्यादा की कमी

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (तीसरी तिमाही) में कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम कर संग्रह में 5.2 फीसदी की गिरावट आई है, वहीं व्यक्तिगत आयकर संग्रह में मामूली इजाफा हुआ है। इससे सरकार के लिए आयकर की दरों में कटौती करना कठिन हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि कंपनियों से मिलने वाला अग्रिम कर में कमी अर्थव्यवस्था में नरमी, कॉरपोरेट कर में कटौती और केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कटौती की वजह से आई है।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अग्रिम कॉरपोरेट कर घटकर 0.73 लाख करोड रुपये रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 0.77 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह व्यक्तिगत आयकर का अग्रिम भुगतान 0.33 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इस दौरान 0.24 लाख करोड़ रुपये रहा।

15 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि महज 0.7 फीसदी रही जिसका मतलब है कि पूरे साल के 13.35 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर संग्रह में अब तक की गई वसूली की तुलना में आधे से ज्यादा का इजाफा होना चाहिए। तीसरी तिमाही में भुगतान के बाद अग्रिम कर संग्रह 2.51 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.47 लाख करोड़ रुपये था। कर विभाग ने अप्रैल-सितंबर 2019-20 तिमाही में 2.2 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह किया था।

कर संग्रह में नरमी

- तीसरी तिमाही में शुद्ध संग्रह 0.7 फीसदी बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपये रहा
- पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अग्रिम कर (कॉरपोरेट) 5.2 फीसदी घटकर 0.73 लाख करोड़ रुपये रहा
- अग्रिम कर (आयकर) संग्रह 0.33 लाख करोड़ रुपये रहा
- इस साल अब तक सकल कर संग्रह 8.34 लाख करोड़ रुपये रहा

1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य!

कर संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं होने के आसार के बीच वित्त मंत्रालय कर वसूली मशीनरी को और अधिक सक्रिय कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने 2019-20 के बचे चार महीनों में हर महीने 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के अनुसार राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। पृष्ठ 4

सरकार के एक सूत्र ने कहा, 'इस साल अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.34 लाख करोड़ रुपये है जबकि पिछले साल समान अवधि में 7.96 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ था। शुद्ध कर संग्रह करीब 6.75 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में 6.7 लाख करोड़ रुपये रहा था।' दूसरी ओर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रिफंड में 26.6 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

कर संग्रह के आंकड़ों को देखते हुए प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य में कटौती करने की जरूरत है। सरकार के लिए मुश्किल यह भी है कि केंद्र का राजकोषीय घाटा अक्टूबर में ही लक्ष्य से 2.4 फीसदी अधिक पहुंच गया है। सूत्रों ने कहा, 'कुल कर संग्रह में कमी आई है। हमने अभी कर संग्रह में कमी का ठोस विश्लेषण नहीं किया है लेकिन यह कहना कठिन है कि संग्रह में कमी केवल कॉरपोरेट कर में कटौती की वजह से आई है या अन्य कारण हैं।'

कुल कर संग्रह में करीब 45 फीसदी अग्रिम कर से और शेष स्रोत पर कर कटौती एवं अन्य स्रोतों से आती है। बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.5 फीसदी बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था जबकि अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 15 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई में पेश संपूर्ण बजट में कर संग्रह में 45,000 करोड़ रुपये की कटौती करने के बाद यह लक्ष्य तय किया गया था। पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से 53,000 करोड़ रुपये रहा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बार कर संग्रह और भी कम रह सकता है।

बिक्री लक्ष्य से चूक सकती है यूनिलीवर

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 17 दिसंबर

उपभोक्ता सामान बनाने वाली दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी यूनिलीवर भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल के कारण कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 में बिक्री के अनुमानों में कटौती की है। बिक्री में मात्रा के लिहाज से कंपनी के लिए भारत सबसे बड़ा और कीमत के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

कंपनी ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण एशिया में सुस्ती और पश्चिम एशिया में कमजोर मांग के कारण 2019 और 2020 की पहली छमाही में उनकी बिक्री अनुमान से कम रहेगी। इस घोषणा के बाद एम्सटर्डम में कंपनी का शेयर 6.6 फीसदी लुढ़क गया जो तीन साल में सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि भारतीय निवेशकों ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई।

- बिक्री अनुमानों में की कटौती
- दक्षिण और पश्चिम एशिया में सुस्ती
- 6.6 फीसदी गिरा कंपनी का शेयर
- भारतीय निवेशकों ने नहीं दी तवज्जो

भारत में यूनिलीवर की सहयोगी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) का शेयर बीएसई में 0.48 फीसदी की गिरावट के साथ 1,964.45 रुपये पर बंद हुआ। एचयूएल की 67 फीसदी हिस्सेदारी है। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था और कंपनी प्रबंधन ने भी हाल फिलहाल बिक्री के पटरी पर नहीं लौटने की संभावना जताई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में शोध विश्लेषक नवीन त्रिवेदी ने कहा, 'पिछले डेढ़ महीने से एचयूएल के शेयर की कीमतों में गिरावट आई है और यह 2,179 रुपये के स्तर से 1,964 रुपये पर आ चुका है। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के नतीजों के दौरान प्रबंधन ने कहा था कि घरेलू एफएमसीजी बाजार में चुनौतियां बरकरार हैं और शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बिक्री आधी रह गई है। इसलिए मुझे आज के वैश्विक घटनाक्रम पर बाजार की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ है।'

लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारत में सुस्ती का दौर लंबे समय तक रह सकता है और यूनिलीवर की बिक्री का अनुमान इसका संकेत है। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के एफएमसीजी विश्लेषक नितिन गुप्ता ने कहा, 'बाजार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में मांग पटरी पर लौटेगी लेकिन स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और नंवबर में स्थिति बदतर हुई है। सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ग्रामीण इलाकों में मांग लगातार कम हो रही है।'

बाजार शोध एजेंसी नीलसन ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री के 5 फीसदी से कम रहने का अनुमान जताया है जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 5 फीसदी के आसपास थी। एजेंसी ने साथ ही कहा था कि सितंबर तिमाही में ग्रामीण इलाकों में बिक्री वृद्धि 2 फीसदी रही थी जो सात साल के सबसे कम है और आने वाले महीनों में भी यह इसी स्तर पर बनी रहेगी।

एचयूएल की कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों का योगदान 40 फीसदी है जबकि उद्योग का औसत 33 से 35 फीसदी है। यही वजह है कि अगर ग्रामीण उपभोक्ता ने खर्च में कमी की तो दूसरी कंपनियों की तुलना में एचयूएल पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि कंपनी के चेयनमैन और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता ने अक्टूबर में संकेत दिया था कि ग्रामीण इलाकों में आय हस्तांतरण अहम होगा।

उन्होंने कहा, 'एफएमसीजी की वृद्धि दर में कमी का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण इलाकों में मांग में कमी है। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सुस्ती है और सरकार ने मांग बढ़ाने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई नीतिगत उपायों की घोषणा की है। इनका ग्रामीण इलाकों पर क्या प्रभाव होगा, यह देखना अहम होगा।'

सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड

सेंसेक्स में उछाल

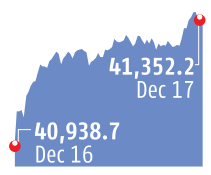

निफ्टी की चाल

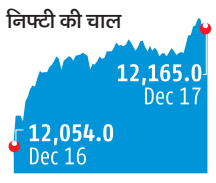

भागीदारी से रहे दूर
मौजूदा स्तर से डर रहे हैं वृहद बाजार सूचकांक तेजी में नहीं शामिल

	मिडकैप	स्मॉलकैप
सर्वश्रेष्ठ स्तर **	18,321	20,183
मौजूदा स्तर	14,818	13,393
गिरावट	-19.1%	-33.6%

निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर (7 दिसंबर तक)

चढ़े शेयर	कीमत रु. में	तेजी* (%)
टाटा स्टील	439.4	4.4
भारती एयरटेल	440.0	4.3
वेदांत	152.4	3.5
हिंडाल्को	213.7	3.4
टाटा मोटर्स	180.2	3.0

लुढ़के शेयर	कीमत रुपये में	गिरा* (%)
सन फार्मा	429.1	-1.4
गेल इंडिया	119.8	-1.2
टाइटन	1,157.4	-0.7
एचयूएल	1,961.4	-0.7
बजाज ऑटो	3,199.1	-0.7

उछलने और फिसलने वाले शेयर
कॉर्पोरेट कर में कटौती की घोषणा के बाद बैंक रहे आगे, तेजी की अगुआई कर रही आरआईएल

निफ्टी 50

19 सितं. 2019	17 दिसं. 2019	
10,704.8	12,165.0	1460.2

इन्होंने दिया योगदान

सबसे आगे		पिछड़े	
आरआईएल	242.7	इन्फोसिस	-79.8
आईसीआईसीआई	234.0	पावर ग्रिड	-7.2
एचडीएफसी	184.5	हीरो मोटोकॉर्प	-7.0
एचडीएफसी बैंक	172.0	गेल इंडिया	-6.7
ऐक्सिस बैंक	89.6	एमऐंडएम	-3.2

* एक दिन में बदलाव, ** जनवरी 2018, संकलन: बीएस रिसर्च ब्यूरो, स्रोत: ब्लूमबर्ग/एक्सचेंज

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को लेकर तनाव कम होने तथा विदेशी कोषों के सतत प्रवाह के बीच मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 413.45 अंक चढ़कर रिकॉर्ड 41,401.65 के उच्च स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 111.05 अंक चढ़कर 12,182.75 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में करीब एक-एक फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत से वैश्विक बाजारों में भी तेजी का रुख देखा गया। एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई। शांघाई कंपोजिट में 1.27 फीसदी और ताइवान ताईएक्स 1.32 फीसदी बढ़त पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की धारणा सुधरने के बावजूद विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में मुनाफावसूली की है। दिसंबर में उन्होंने 1,306 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की है। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दिसंबर में 3,474 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सितंबर में कॉरपोरेट कर में कटौती की घोषणा के बाद से ही बाजार में मजबूत तेजी का रुख बना हुआ है। 19 सितंबर से अब तक बाजार की तेजी में बैंकों को अहम योगदान रहा है और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और ऐक्सिस बैंक की अगुआई में निफ्टी की बढ़त में 46 फीसदी से ज्यादा का योगदान दिया। उच्च कर दायरे में आने की वजह से कॉरपोरेट कर में कटौती के बड़े लाभार्थियों में बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां प्रमुख हैं। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक अब भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से क्रमशः 19 फीसदी और 33 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि हालिया तेजी सभी क्षेत्रों में नहीं दिख रही है। इस साल अब तक मिड कैप 6 फीसदी और स्मॉलकैप 8.9 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक कारकों के अनुकूल होने से अब घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार और 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर निवेशकों की नजर रहेगी। ***सुंदर सेतुरामन और जश कृपलानी***

दिल्ली में ठंड से गरम हुआ हीटर और गीजर का बाजार

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

दिल्ली में कंपकंपाती ठंड से हीटर, गीजर और पानी गर्म करने की रॉड की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आगे भी ठंड इसी तरह जारी रहने पर इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। बीते दो साल इन कारोबारियों के लिए अच्छे नहीं रहे। दिल्ली का भगीरथ प्लेस बाजार हीटर, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रिकल सामान के कारोबार का प्रमुख केंद्र है। कारोबारियों के मुताबिक भगीरथ प्लेस में 300 से अधिक कारोबारी हीटर, गीजर, पानी गर्म करने की रॉड आदि का कारोबार करते हैं, जिनका सालाना कारोबार 25 से 30 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

भगीरथ प्लेस के कारोबारी प्रदीप कोचर ने बताया कि ठंड बढ़ने के कारण दिल्ली में इस सप्ताह पिछले हफ्ते की तुलना में हीटर, गीजर, पानी गर्म करने की रॉड की बिक्री 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इलेक्ट्रिकल कारोबारी रविंद्र गुप्ता ने कहा कि जीएसटी लागू होने और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने के कारण बीते दो साल कारोबार के लिए अच्छे नहीं रहे। इस साल बीते कुछ दिनों से अब अच्छी ठंड पड़ने से रूम हीटर की मांग में सबसे ज्यादा तेजी आई है। पहाड़ी राज्यों से भी रूम हीटर, गीजर की मांग आ रही है।

दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत आहूजा कहते हैं कि बीते दो-तीन साल से ठंड कम पड़ रही है। इस साल बीते कुछ दिनों से अचानक ठंड बढ़ गई है। ऐसे में इस साल पिछले साल से हीटर, गीजर, पानी गर्म करने की रॉड की बिक्री 15 से 20 फीसदी बढ़ने की संभावना है। बाजार में रूम हीटर 500 रुपये लेकर 2,000 रुपये, गीजर 4,000 रुपये से 10,000 रुपये और पानी गर्म करने की रॉड 300 रुपये से लेकर 500 रुपये में बिक रही है।

- दिल्ली में 16 साल में पहली बार दिन का पारा सामान्य से 10 डिग्री कम
- पिछले सप्ताह से इस हफ्ते बिक्री में 40 फीसदी से ज्यादा इजाफा
- कारोबारियों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद

जीएसटी अनुपालन में सख्ती का इरादा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

सरकार ने फर्जी बिल लगाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड में फर्जीवाड़े से निपटने के लिए मुहिम तेज कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को होने वाली बैठक में कर अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के उपायों पर विचार किया जाएगा। परिषद की प्रस्तावित बैठक में कर अनुपालन नहीं करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने और नकली बिल देने पर गिरफ्तारी जैसे कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं।

विधि समिति ने सरकार के राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कर प्रवंचना में संलिप्त सभी कारोबारों का आईटीसी भुगतान रोकने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने कानून में एक प्रावधान लाकर आयुक्त या अधिकारी को आउटपुट टैक्स

इन पर होगा विचार

- सरकार एवं निजी तौर पर संचालित लॉटरी पर समान दर पर विचार संभव
- राजस्व वृद्धि पर अधिकारियों की समिति देगी प्रस्तुति
- रियल एस्टेट पर मंत्री समूह की रिपोर्ट

या आईटीसी के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रखी पूरी रकम या इसका एक हिस्सा रोकने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में राजस्व में इजाफा करने के उपायों पर चर्चा के अलावा कानूनी मामले कम करने के लिए एक लोक शिकायत इकाई की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा,'उद्योग जगत ने सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र लिखकर राजस्व संग्रह में कमी दूर करने पर ध्यान देने की मांग की है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी। परिषद की बैठक में इन विषयों पर विचार होगा।'

अधिकारी ने कहा कि कारोबारियों द्वारा फर्जी बिल लगाने से कर नुकसान होता है, लिहाजा जो लेनदेन वास्तव में हुए ही नहीं हैं, उनके लिए संग्रहित कोष से भुगतान करना होता है। अधिकारी ने कहा कि इससे सीधे तौर पर सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

परिषद राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार करेगा। कर आधार बढ़ाने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने और कर अनुपालन बढ़ाने के लिए अधिकारी समिति और मंत्रियों का समूह परिषद में ये उपाय विचार के लिए रखेंगे।

परिषद के एजेंडा पत्र में कहा गया है, 'जीएसटी प्रभावी होने के बाद कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए कई बार संशोधन हो चुके हैं। कर छूट की सीमा बढ़ाने और कंपोजिशन स्कीम आदि में बदलाव से जीएसटी राजस्व संग्रह पर नकारात्मक असर हुआ है। अनुमानिज राजस्व संगह और वास्तविक रकम की जरूरत के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की दरकार है।'

खबरों में रहे स्टॉक

फेडरल-मुगल गोएट्ज (इंडिया)

खुली पेशकश के लिए शेयरों का मूल्यांकन 608.46 रुपये बरकरार

₹ 553.80 पिछला बंद भाव
₹ 661.75 आज का बंद भाव
▲ 19.49 %

एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज

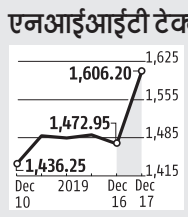

शेयर पुनर्खरीद प्रस्ताव पर विचार के लिए बोर्ड बैठक 23 दिसंबर को

₹ 1,472.95 पिछला बंद भाव
₹ 1,606.20 आज का बंद भाव
▲ 9.05 %

एवेन्यू सुपरमार्ट्स

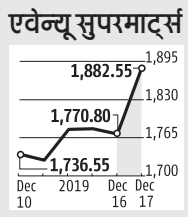

एसऐंडपी बीएसई 100 सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 1,770.80 पिछला बंद भाव
₹ 1,882.55 आज का बंद भाव
▲ 6.31 %

टाटा स्टील

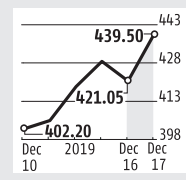

सिटी ने बरकरार रखी रेटिंग, कहा इस्पात की वैश्विक कीमत बढ़ सकती है

₹ 421.05 पिछला बंद भाव
₹ 439.50 आज का बंद भाव
▲ 4.38 %

कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स

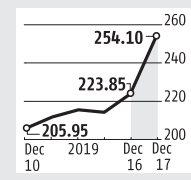

पुणे में 205 करोड़ रुपये बुकिंग राशि के साथ बेचे 500 अपार्टमेंट

₹ 223.85 पिछला बंद भाव
₹ 254.10 आज का बंद भाव
▲ 13.51 %

संक्षेप में

पतंजलि को रुचि सोया संग सौदे के लिए समय

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कर्ज बोझ तले दबी खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया का 4,350 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने का सौदा पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय और दे दिया है। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाले एनसीएलएटी के तीन सदस्यीय पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद की अर्जी पर सौदे को पूरा करने की समयसीमा मंगलवार को 23 दिसंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले अपीलीय न्यायाधिकरण ने समयसीमा को बढ़ाकर 16 दिसंबर तक किया था। पतंजलि आयुर्वेद को शुरू में इस अधिग्रहण को पूरा करने के लिए 21 नवंबर तक का समय दिया गया था। *भाषा*

जेपी इन्फ्राटेक मामले में एनबीसीसी की बोली मंजूर

जेपी इन्फ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं ने कर्ज में डूबी रीयल्टी कंपनी को ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत खरीदने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी की बोली को मंजूरी दे दी है। वित्तीय कर्जदाताओं में बैंक तथा मकान खरीदार शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 फीसदी मतदान से मंजूरी दे दी है। यह जेपी इन्फ्राटेक के लिए खरीदार तलाशने को लेकर बोली प्रक्रिया का तीसरा दौर है। कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में अगस्त 2017 में गई। मामले के सफल समाधान से 20,000 मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। *भाषा*

दो और निवेशक जेट में इच्छुक

सिनर्जी ने कारोबारी योजना का मसौदा सौंपा, नए निवेशकों पर सीओसी लेगी निर्णय

सुब्रत पांडा
मुंबई, 17 दिसंबर

बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने आज दिवालिया ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि इस विमानन कंपनी के पुनरुद्धार में दो अन्य विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब तक जेट एयरवेज के लिए एकमात्र बोलीदाता दक्षिण अमेरिका की विमानन कंपनी सिनर्जी ग्रुप थी।

आरपी ने नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को यह भी बताया है कि उन्हें सिनर्जी ग्रुप से कारोबारी योजना का मसौदा करीब एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ। जेट एयरवेज के लिए समाधान योजना जमा कराने की अंतिम समय-सीमा 16 दिसंबर थी।

नागर विमानन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2020 तक सर्दियों के लिए स्लॉट का आवंटन पूरा हो चुका है जबकि गर्मियों के लिए स्लॉट का आवंटन अभी खुला है। नवंबर 2020 तक केवल एयर इंडिया को गर्मियों के लिए स्लॉट का आवंटन हुआ था।

हालांकि नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि सिनर्जी ग्रुप से कारोबारी योजना मिलने के बाद ही जेट एयरवेज के स्लॉट आवंटन पर विचार किया जाएगा। जेट एयरवेज के लेनदार और आरपी की लेनदारों की समिति के साथ बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया कि समाधान योजना जमा कराने के लिए सिनर्जी ग्रुप को तीसरा विस्तार दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। साथ ही इस विमानन कंपनी में दो नए विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी के बारे में भी चर्चा की गई।

ट्रिब्यूनल ने आरपी से कहा था कि यदि सिनर्जी ग्रुप के साथ बातचीत विफल रहती है तो वे अन्य निवेशकों पर भी विचार कर सकते हैं। यदि लेनदारों की समिति इस विमानन कंपनी में दिलचस्पी दिखाने वाले दो नए निवेशकों पर गंभीरतापूर्वक विचार करती है तो उसे पूरी बोली प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। इसके तहत दोनों पक्षों को अभिरुचि पत्र जमा कराने होंगे और उसका आकलन आरपी द्वारा किया जाएगा।

आरपी ने एनसीएलटी को यह भी सूचित किया है कि 19 दिसंबर को एनसीएलटी के सामने सिनर्जी ग्रुप का एक प्रतिनिधि पेश होगा ताकि ट्रिब्यूनल की आशंकाओं को दूर किया जा सके। ट्रिब्यूनल यह समझना चाहता है कि जेट एयरवेज के पुनरुद्धार को लेकर सिनर्जी ग्रुप कितना गंभीर है।

सिनर्जी चाहती है कि नागर विमानन मंत्रालय जेट एयरवेज के स्लॉट के मुद्दे को स्पष्ट करे और बताए कि विमानन कंपनी के अधिग्रहण के बाद वे उसके साथ बरकरार रहेंगे अथवा नहीं।

नागर विमानन मंत्रालय ने आरपी के उस शपथ पत्र पर अपना जवाब दे दिया है जिसमें स्लॉट आवंटन के सदंर्भ में कुछ रियायत की मांग की गई थी।

आरपी जेट एयरवेज के लिए कॉरपोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया शुरू करने में विस्तार के लिए एनसीएलटी में एक शपथ पत्र पहले ही दायर कर चुका है। इस प्रक्रिया के लिए 180 दिनों की अवधि 16 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के तहत शुरुआती 180 दिनों की अवधि पूरी होने पर 90 दिनों का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकता है।

जेट एयरवेज के आरपी को वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों और कर्मचारियों से अब तक 36,000 करोड़ रुपये के बकाये के लिए दावे प्राप्त हुए हैं।

जेट एयरवेज के लिए बोली

- अब तक जेट एयरवेज के लिए एकमात्र बोलीदाता सिनर्जी ग्रुप था
- जेट एयरवेज के लिए समाधान योजना जमा कराने की अंतिम समय-सीमा 16 दिसंबर थी
- सिनर्जी चाहती है कि नागर विमानन मंत्रालय जेट एयरवेज के स्लॉट के मुद्दे को स्पष्ट करे

आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगी सिप्ला

सोहिनी दास
मुंबई, 17 दिसंबर

प्रमुख औषधि कंपनी सिप्ला केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। इसके तहत कंपनी न केवल जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगी बल्कि उसके लिए पूरी स्वास्थ्य सेवा वातावरण को बेहतर करेगी। साथ ही कंपनी इस कार्यक्रम के तहत बिक्री के लिए दवाओं की अलग से ब्रांडेड पैकेजिंग कराने की भी योजना बना रही है और इस योजना से संबद्ध बीमा कंपनियों एवं अस्पतालों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है।

कंपनी ने एचआईवी-एड्स के लिए एक डॉलर प्रति दिन से कम कीमत पर दवा उलब्ध कराते हुए बाजार उथल-पुथल मचा दिया था। अब उसने सस्ती दवाओं पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। सिप्ला के कार्यकारी उपाध्यक्ष और भारतीय कारोबार के प्रमुख निखिल चोपड़ा ने कहा, 'हम उस क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं जहां हम डॉक्टर से लेकर नर्स, पैरामेडिक्स, आपूर्ति श्रृंखला और उपलब्धता में सुधार सहित पूरे स्वास्थ्य सेवा वातावरण में संसाधनों को अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार के साथ साझेदारी कर सकते हैं।'

चोपड़ा ने कहा कि कंपनी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आयुष्मान भारत के प्रमुख इंदु भूषण से जल्द मुलाकात करने की योजना बनाई है। वह एक ऐसे मॉडल के लिए बातचीत करेंगे जहां सिप्ला जैसी कोई औषधि कंपनी इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकती है ताकि सस्ती दवाओं तक पहुंच और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके तहत जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की सूची की पहचान की जाएगी जिसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, इंजेक्शन आदि दवाएं शामिल होंगी। कंपनी इन दवाओं की आपूर्ति आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों को करेगी। इन दवाओं की पैकेजिंग सिप्ला की सामान्य पैकेजिंग से अलग हो सकती है।

सिप्ला बाजार के निचले स्तर पर संभावनाएं तलाश रही है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 15 लाख नए रोगी और 85 लाख बिना गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगी सामने आए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा पर खर्च में 40 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। ईवाई के आकलन के अनुसार, आयुष्मान भारत के लिए बाजार के आकार में वृद्धि वित्त वर्ष 2021 तक 2.2 अरब डॉलर हो सकती है।

इनफॉर्मा मार्केट्स के भारत में एमडी योगेश मुद्रास ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा कहीं अधिक व्यापक होगा और उसके दायरे में काफी रोगी पंजीकृत होंगे। इस प्रकार यह भारतीय औषधि कंपनियों के लिए भविष्य की वृद्धि का एक प्रमुख क्षेत्र बन सकता है।

हालांकि आयुष्मान भारत फिलहाल अस्पतालों तक सीमित है। सिप्ला का कहना है कि उसके पास करीब 60 वितरक ऐसे हैं जो अस्पतालों को विशेष तौर पर आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रेस्क्रिप्शन कारोबार के लिए करीब 3,000 वितरक और जेनेरिक कारोबार के लिए करीब 5,000 वितरक मौजूद हैं। कंपनी के जेनेरिक कारोबार का आकार करीब 1,500 करोड़ रुपये है और गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की बिक्री के संदर्भ में सिप्ला अग्रणी घरेलू औषधि कंपनी है।

लंदन में ओला से जुड़े 10,000 ड्राइवर

राइड-हेलिंग फर्म ओला ने कहा है कि लंदन में महज तीन महीने के दौरान करीब 10,000 से अधिक ड्राइवरों ने उसके प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। साथ ही सॉफ्टबैंक के निवेश वाली इस कंपनी ने कहा है कि उसने अपनी तरह की पहली पेशकश की है जिसके तहत सेवाएं शुरू होने के बाद पहले दो महीने के लिए ड्राइवरों से शून्य कमीशन लिया जाएगा। इससे उन्हें ओला प्लेटफॉर्म से 100 फीसदी आय हासिल होगी।

ओला के अंतरराष्ट्रीय कारोबार प्रमुख सिमोन स्मिथ ने कहा, 'हम लंदन में ड्राइवरों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से काफी खुश हैं। इस शहर में ड्राइवरों के साथ हमारी रहेक बातचीत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने का अवसर दिखा जहां उनके साथ-साथ ग्राहकों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।' उन्होंने कहा, 'हम यह देखकर काफी उत्साहित हैं कि ड्राइवरों के बीच रेफरल और बातचीत के जरिये इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण हुआ है। इससे ओला प्लेटफॉर्म में उनके भरोसे और हमारी पेशकश के आकर्षण का पता चलता है।' *बीएस*

ब्रोकर चाहते हैं कि केवाईसी के लिए आधार के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो

ब्रोकर चाहें, आधार से केवाईसी

सचिन मामबटा
मुंबई, 17 दिसंबर

ब्रोकरों को नए ग्राहक तेजी से जोड़ने के लिए नो यॉर क्लाइंट (केवाईसी) के लिए आधार के इस्तेमाल पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने का इंतजार है।

शुरू में वे केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन के जरिये पूरा करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करते थे। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं लंबी हो गई हैं। इस अदालती फैसले में कंपनियों और निजी इकाइयों द्वारा आधार का इस्तेमाल रोक दिया गया था।

उन्होंने कहा कि यदि ऑनलाइन पर फिर से अमल किया जाता है तो ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया तेज होगी। सैमको सिक्योरिटीज के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी जिमीत मोदी ने कहा, 'जब यह (केवाईसी) प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ग्राहक को महज 15 मिनट में अपने साथ जोड़ा जा सकेगा।'

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक सतीश मेनन ने कहा, 'मौजूदा समय में, केवाईसी प्रक्रिया ऑफलाइन है। यदि हमें फिर से आधार के जरिये ऑनलाइन केवाईसी की अनुमति मिलती है तो यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।'

एक सूत्र के अनुसार, आधार के जरिये ऑनलाइन केवाईसी की अनुमति एक महीने के अंदर दी जा सकती है। सेबी ने 5 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें आधार के जरिये इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (ई-केवाईसी) के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। उसने कहा था कि यह कार्य केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) के जरिये किया जा सकेगा, जो यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत है।

सर्कुलर में कहा गया, 'सेबी के साथ पंजीकृत बिचौलियों/म्युचुअल फंड वितरकों (जो केयूए के जरिये आधार प्रमाणन सेवाएं चाहते हैं) को किसी एक केयूए के साथ समझौता करना होगा और स्वयं को उप-केयूए के तौर पर यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत कराना होगा। केंद्र सरकार/यूआईडीएआई के साथ पंजीकरण की सूचना पर, केयूए और उप-केयूए को प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के लिए आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया अपनानी होगी।'

एक अन्य ब्रोकिंग फर्म के अधिकारी ने कहा कि ताजा पहलों के बावजूद आधार के इस्तेमाल को लेकर कुछ अनिश्चितता है और इस संबंध में और अधिक स्पष्टता से ग्राहक जोड़ने में लगने वाले समय में कमी लाई जा सकेगी।

खबरों के अनुसार ब्रोकरेज उद्योग की कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आधार सत्यापन का अन्य स्वरूप ईसाइन है जिसका इस्तेमाल पिछले सप्ताह बंद कर दिया गया। इस बारे में सूचना प्राप्त करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि ब्रोकरों को बाद में बताया गया कि सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। ब्रोकिंग उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि केवाईसी प्रक्रिया में तेजी आने से उन्हें कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से अलग हुए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। ग्राहक परिसंपत्तियों के अनुचित इस्तेमाल की वजह से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक्सचेंज से प्राप्त आंकड़े के अनुसार नवंबर तक कार्वी के पास 282,000 सक्रिय ग्राहक थे।

सेबी, कार्वी को इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेश का कोई जवाब नहीं मिला है।

आधार के इस्तेमाल पर नई शुरुआत

- ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि केवाईसी की तेज प्रक्रिया से उन्हें कार्वी के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में मदद मिलेगी
- सेबी ने 5 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें आधार के जरिये इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (ई-केवाईसी) के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी
- 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऑनलाइन केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल रोक दिया गया था
- केंद्र सरकार ने इसके इस्तेमाल को पुनः शुरू किए जाने का कदम उठाया है

फोरेंसिक ढांचे पर कंपनियों का जोर

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

हम अक्सर अपराध की खबरों को देखते समय फोरेंसिक जांच के बारे में सुनते हैं। यह जांच अब ऑडिट उद्योग में आम बात हो गई है। धोखाधड़ी के मामले बढ़ने से कंपनियां सामान्य ऑडिट से अलग प्रक्रियाओं के जरिये अतिरिक्त सतर्कता के लिए ऑडिट कंपनियों तक पहुंच बना रही हैं। कंपनियां 'कल की सुर्खियां' बनने को लेकर सजगता बढ़ा रही हैं और ऑडिटरों से जोखिम वाले क्षेत्रों को दूर करने को कह रही हैं।

धोखाधड़ी-रोधी ढांचे को बढ़ावा

पिछले दो वर्षों में ईवाई इंडिया ने कंपनियों में फोरेंसिक ढांचा तैयार करने के लिए 7-8 बड़े समझौते किए। ईवाई इंडिया में फॉरेंसिक ऐंड इंटेग्रिटी सर्विसेज के पार्टनर योगेन वैद्य ने कहा, 'शुरू में हमारे पास साल में ऐसे एक या दो से ज्यादा समझौते नहीं होते थे। बड़ी तादाद में लोग धोखाधड़ी रोकने की दिशा में सक्रिय हो रहे हैं, और वे धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

इसमें एक आचार संहिता स्थापित करना और नियंत्रण प्रणालियों को अपग्रेड करना शामिल है और इस सब कार्य में एक वर्ष तक का समय लग सकता है। ईवाई ने अपने कुछ बड़े ग्राहकों के लिए भ्रष्टाचार, प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रणालियों के मामलों के संदर्भ में 'हीट मैच' बनाने शुरू किए हैं। यह पहल सामान्य जोखिम आकलन से परे है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेल एवं गैस और खनन समेत सभी क्षेत्रों की कंपनियां ऐसी सेवाएं तलाश रही हैं।

ऑडिट कंपनियां नौकरी पर रखे जाते वक्त वरिष्ठ अधिकारियों की पृष्ठभूमि की जांच पर भी ध्यान बढ़ा रही हैं। इस तरह की जांच न सिर्फ अधिकारी की पिछली जिंदगी से अवगत होने बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी की जा रही हैं कि व्यक्ति कंपनी की संस्कृति एवं प्रबंधन के लिहाज से अनुकूल हो।

फोरेंसिक कार्य में आ रही तेजी

सभी ऑडिट कंपनियों की फोरेंसिक टीमों ने पिछले साल व्हिसलओवर शिकायतों में भी बड़ी तेजी दर्ज की। जहां पहले कुछ महीनों में महज 4-5 शिकायतें मिलती थीं, वहीं अब महज एक सप्ताह में इस तरह की 4-5 शिकायतें मिल जाती हैं। कंपनियां व्हिसलब्लोअर हॉटलाइंस स्थापित कर रही हैं, क्योंकि वे धोखाधड़ी के जोखिमों से ज्यादा अवगत हो रही हैं और अपनी प्रणाली में कमजोरियां महसूस कर रही हैं। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर निखिल बेदी ने कहा, 'कई कंपनियां समस्याओं से संबंधित नीतियों की पहचान एवं उन पर अमल के लिए प्राथमिक विकल्प के तौर पर व्हिसलब्लोअर हॉटलाइंस का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारा मानना है कि व्हिसलब्लोअर हॉटलाइंस की उपस्थिति से कंपनी में अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।'

आईबीसी की पेशकश के बाद परिणाम वास्तविक बनाने के लिए स्वतंत्र निदेशकों, रिजोल्यूशन पेशेवरों के बीच फॉरेंसिक जांच की मांग बढ़ी है। कंपनियां सांविधिक ऑडिट से व्यापक परिणाम की उम्मीद कर रही हैं।

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी विशेष चंडोक ने कहा, 'कंपनियां बेहद खास एवं भरोसेमंद उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। धोखाधड़ी की जांच के संदर्भ में ऑडिट पर्याप्त नहीं रह गया है।'

मौजूदा समय में धोखाधड़ी के इतने ज्यादा मामले प्रकाश में क्यों आ रहे हैं? विश्लेषकों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में मंदी से कंपनियों की कई कमजोरियों को उजागर किया है। वैद्य ने कहा, 'मंदी एक चुनौतीपूर्ण दौर होता है। लोग इस दौरान शॉर्टकट अपनाते हैं। इससे धैर्य और सहनशीलता का अभाव बढ़ रहा है।'

धोखाधड़ी रोकने की कवायद तेज

- कंपनियां नियंत्रण प्रणालियों को अपग्रेड करने पर ध्यान दे रही हैं
- कई कंपनियां व्हिसलब्लोअर हॉटलाइंस स्थापित कर रही हैं
- धोखाधड़ी की जांच के संदर्भ में ऑडिट पर्याप्त नहीं रह गया है।
- नई नियुक्तियों के वक्त पृष्ठभूमि की गहन जांच पर रहेगी नजर

ईआर नीति के लाभ के लिए पांच तेल क्षेत्रों का चयन

ज्योति मुकुल
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

केयर्न वेदांत के भाग्यम क्षेत्र और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के चार क्षेत्रों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की तीव्र सुधार (ईआर) नीति के तहत आर्थिक प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्वीकृत किया गया है। हालांकि केयर्न के प्रमुख क्षेत्र मंगला और ओएनजीसी के झालोरा क्षेत्र का भाग्य हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के फैसले पर टिका हुआ है जिसमें यह तय किया जाना है कि वे इस नीति के तहत लाभ पाने योग्य हैं या नहीं।

मंगला और झालोरा की पात्रता को लेकर यह विवाद इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि डीजीएच को अभी इस बारे में निर्णय लेना है कि क्या ईआर तकनीकों के इस्तेमाली वाली क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी) को नीति के क्रियान्वयन से पहले स्वीकृत किया गया था।

ईआर नीति सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति का मकसद तेल एवं गैस के लिए रिकवरी दर बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था।

हालांकि इस नीति का लाभ लगभग 215 क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कंपनियों ने ईआर और आईआर तकनीकों को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना है, क्योंकि ये तकनीकें लंबे समय और पूंजीगत खर्च वाली कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।

इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'देश के कुल उत्पादन का 95 प्रतिशत हिस्सा 66 तेल क्षेत्रों से प्राप्त होता है जबकि 149 क्षेत्र कच्चे तेल के 5 प्रतिशत से भी कम का उत्पादन करते हैं।'

केयर्न के लिए, नीति के तहत प्रोत्साहन 10 वर्षों के दौरान लगभग 60 करोड़ डॉलर रहेगा। नीति में कच्चे तेल उत्पादन पर तेल उद्योग के उपकर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सरकार प्रत्येक बैरल तेल उत्पादन पर 20 प्रतिशत उपकर वसूलती है। यह मौजूदा समय में 12 डॉलर प्रति बैरल बैठता है। नीति के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन की पात्रता के लिए क्षेत्रों को कम से कम तीन वर्ष तक वाणिज्यिक परिचालन करना चाहिए। यह रियायत गैर-पारंपरिक तेल उत्पादन के मामले में उत्पादन के शुरू से उपलब्ध है।

प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में, रिकवरी बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किए जाने पर 75 प्रतिशत रॉयल्टी की छूट दी गई है। वहीं गैर-पारंपरिक गैस उत्पादन के लिए 75 प्रतिशत की छूट पूरे उत्पादन पर है। रॉयल्टी दर मौजूदा समय में तेल कीमत की 20 प्रतिशत है।

बीएस बातचीत

अच्छे मूल्यांकन के लिए क्षमता वृद्धि में सुधार जरूरी

एस्सार स्टील के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल **सतीश कुमार गुप्ता** ने आगामी चुनौतियों के बारे में **ईशिता आयान दत्त** के साथ विस्तार से बातचीत की। गुप्ता ने दो साल से ज्यादा समय तक दिवालिया प्रक्रिया का प्रबंधन किया। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

आईबीसी के संदर्भ में एस्सार स्टील की समाधान प्रक्रिया कितनी महत्त्वपूर्ण है?
जून 2017 में आरबीआई द्वारा आईबीसी के तहत दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए सौंपे गए 12 खातों में शामिल एस्सार स्टील का समाधान लेनदारों से संबंधित पूंजी की मात्रा और प्रतिशतता के संदर्भ में सबसे बड़ा समाधान है। यह साल के लिए सबसे बड़ा अधिग्रहण सौदा और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी है जिसने दुनिया में सबसे बड़ी इस्पात निर्माता आर्सेलरमित्तल से निवेश आकर्षित किया है।

एस्सार स्टील की कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान आईबीसी को कई बार कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। इस मामले में कौन से मुख्य विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया गया?
समाधान प्रक्रिया के दौरान आईबीसी को दो दौर की मुकदमेबाजी के साथ जूझना पड़ा। इस मामले के संदर्भ में कई मिसालें कायम हुईं।

प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना कितना चुनौतीपूर्ण था?
इस संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें वैल्यू वृद्धि के लिए विभिन्न हितधारकों का प्रबंधन, विभिन्न फोरमों में परिचालन एवं मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं में सुधार शामिल है। शुरुआती अवधि में, बड़ी चुनौती परिचालन को मजबूत बनाने की थी, क्योंकि परिचालन लेनदारों ने दिवालिया प्रक्रिया के शुरू में क्रेडिट सीमाओं पर जोर दिया। मौजूदा नकदी सीमाएं एमएसटीसी द्वारा मुहैया कराई गईं और कुछ अन्य आपूर्तिकर्ता बेहद उपयोगी थे। एनसीएलटी के निर्णय के बाद, परिचालन से प्राप्त रकम का मजबूत इस्पात बाजार का लाभ उठाने के लिए पुन: इस्तेमाल किया गया। इसके परिणामस्वरूप, लेनदारों की समिति और कंपनी के प्रबंधन की मदद से औसत उत्पादन 460,000 टन से बढ़ाकर प्रति महीने 600,000 टन किया जा सका। यह संभावित समाधान आवेदकों के समक्ष यह दिखाने के लिए जरूरी थी कि संयंत्र ऊंचे स्तरों पर परिचालन में सक्षम था जिससे उसके मूल्यांकन को बढ़ावा मिला और ऊंची बोलियों में मदद मिली।

बकायेदारों द्वारा पेश किए गए कुल दावे कितनी रकम के थे?
वित्तीय और परिचालन लेनदारों द्वारा लगभग 82,000 करोड़ रुपये के कुल दावे पेश किए गए थे। दस्तावेजों के आधार पर, लगभग 54,000 करोड़ रुपये के दावों को स्वीकार किया गया था, शेष विवादास्पद थे या उचित कानूनी दस्तावेजों द्वारा पुष्ट नहीं थे।

आप दो समाधान आवेदकों के बीच पात्रता की कसौटी पर बीच में थे। ऐसे में स्थिति कितनी कठिन थी?
सेक्शन 29ए की पात्रता पर निर्णय बेहद चुनौतीपूर्ण था, जिसमें आरपी के तौर पर सीओसी के समक्ष खरा उतरना था। नया क्लॉज होने की वजह से सेक्शन 29ए को पहली बार स्पष्ट किया गया था, और दोनों समाधान आवेदकों को अयोग्य करार देना वाकई एक चुनौतीपूर्ण समय था। सेक्शन 29ए के तहत पात्रता के संबंध में विभिन्न चुनौतियां एक लंबी मुकदमेबाजी वाला मुद्दा बन गईं और इसे सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के साथ सुलझाया गया था जिसमें उसने अयोग्यता के निर्णय को बरकरार रखा था। हालांकि इस प्रक्रिया में बैंकिंग तंत्र को दो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बकाया के तौर पर 7,500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

सीआईआरपी के दौरान एस्सार स्टील का प्रदर्शन कैसा रहा?
सीआईआरपी अवधि के दौरान एस्सार स्टील ने अपना सर्वाधिक उत्पादन और एबिटा दर्ज किया। उसने वित्त वर्ष 2017 में 54.7 लाख टन का रोल्ड इस्पात उत्पादन दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 67.8 लाख टन हो गया और इसका कर्मचारियों समेत सभी हितधारकों को लाभ मिला।

क्या सीआईआरपी के दौरान प्रवर्तकों और प्रबंधन ने सहयोग किया?
हालांकि प्रवर्तकों/संबंद्ध इकाइयों/न्यूमेटल ने विभिन्न कानूनी मंचों पर मुकदमेबाजी पर ध्यान दिया, लेकिन कंपनी का परिचालन आईबीसी के नियमों के अनुसार किया गया था। जैसे ही परिचालन में सुधार आया, प्रवर्तक समूह की सहायक कंपनियों (बिजली, बंदरगाह, शिपिंग आदि से जुड़ी) को भी अच्छा लाभ हुआ।

जीएसटी संग्रह का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

राजस्व विभाग ने दिसंबर से मार्च 2019-20 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का मासिक लक्ष्य 1.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें से भी किसी एक महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह करना होगा। यह लक्ष्य इस वित्त वर्ष में अब तक हुए वास्तविक जीएसटी संग्रह की तुलना में काफी महत्त्वाकांक्षी है।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर बोर्डों के सदस्यों व अधिकारियों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और प्रत्यक्ष कर अधिकारियों से कहा कि कॉर्पोरेशन और व्यक्तिगत आयकर से 13.5 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह सुनिश्चित किया जाए, जो लक्ष्य बजट में 2019-20 के लिए रखा गया है, भले ही सरकार ने कॉर्पोरेशन कर में बदलाव किया है।

वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि कॉर्पोरेशन कर दरों में कटौती की वजह से खजाने में 1.45 लाख करोड़ रुपये कम आने का अनुमान है, लेकिन अधिकारियों को यह साफ कर दिया गया है कि कम संग्रह होने पर इस तर्क को नहीं माना जाएगा।

एक समाचार चैनल के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान पांडेय ने कहा था कि विभाग कॉर्पोरेशन कर में कटौती के बाद 1.45 लाख करोड़ रुपये की चपत लगने के अनुमान को ध्यान में रखते हुए 11 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में से 4 महीने में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा है और यह किसी भी महीने में बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर नहीं गया है।

दरअसल अधिकारियों की राजस्व बढ़ोतरी समिति बुधवार को जीएसटी परिषद के सामने अपनी प्रस्तुति देगा कि राजस्व बढ़ाने की क्या संभावनाएं है।

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी अधिकारियों को कहा गया था कि वह सुनिश्चित करें कि अगर करदाताओं की ओर से जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल किया जाता है तो ई-वे बिल ब्लॉक करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने और पंजीकरण रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उद्योग और कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आपूर्तिकर्ताओं से जीएसटी रिटर्न समय से दाखिल करने को कहें। ऐसा करने में असफल रहने पर खरीदारों को संभवत) इनपुट टैक्स क्रेडिट उन आपूर्तियों पर नहीं मिल सकेगा, जिन पर कर का भुगतान उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया है।

इसके अलावा जीएसटी रिटर्न की सूचना संबंधी आंकड़े आयकर विभाग को मुहैया कराए जाएंगे, जिससे टर्नओवर और आयकर में किसी तरह की विसंगति को पकड़ा जा सके और उचित कर वसूला जा सके। इसके अलावा पुराने बकायों की वसूली के लिए भी अगले 3 महीनों के दौरान अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि राजस्व विभाग अगले 4 महीने के दौरान राजस्व संग्रह बढ़ाने के कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए प्रधान मुख्य आयुक्तों व मुख्य आयुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों के बजट लक्ष्य को हासिल करें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे नियमित रूप से हर सप्ताह फील्ड विजिट करें।

सूत्रों ने कहा कि राजस्व सचिव खुद ही हर सप्ताहांत पर हर क्षेत्र में जाएंगे, जिससे संग्रह की कवायदों की निगरानी की जा सके।

अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि इस तरह से क्षेत्र के दौरे के अभियान के दौरान किसी भी करदाता को समस्या नहीं होनी चाहिए।

यह भी माना जा रहा है कि जीएसटी और आयकर की सूचनाओं व अन्य वित्तीय सौदों को विभागों के साथ साझा किया जाएगा और कर चोरी करने वालों को सामने लाया जा सकेगा। अगर कोई करदाता सही कर सूचना साझा करने में चूक करता है तो उससे पुनरीक्षित रिटर्न दाखिल करने को कहा जाएगा।

कर संग्रह की निगरानी होगी तेज

1.1 लाख करोड़ रु हर माह जीएसटी संग्रह का लक्ष्य

1.25 लाख करोड़ रुपये भी दिसंबर से मार्च तक के 4 महीनों में से एक महीने में जुटाना पड़ेगा

- कॉर्पोरेशन और व्यक्तिगत आयकर से 13.5 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह सुनिश्चित करने के निर्देश
- अधिकारियों से कहा गया है कि यह बहाना नहीं चलेगा कि कॉर्पोरेशन कर में कटौती कर दी गई है

प्रत्यक्ष कर का लक्ष्य स्थिर रखने और कॉर्पोरेशन कर में कटौती के साथ कर अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

ऑनलाइन निगरानी योजना ठंडे बस्ते में

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की निगरानी के लिए सोशल मीडिया एजेंसी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि यूआईडीएआई की ओर से सोशल मीडिया एजेंसी के लिए जारी प्रस्ताव आवेदन (आरएफपी) पर मामला आगे नहीं बढ़ा और अब इस तरह की एजेंसी नियुक्त करने की कोई योजना नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और केएम जोसेफ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का निस्तारण कर दिया। *एजेंसियां*

आईएमएफ घटाएगा वृद्धि का अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भी उन विश्लेषकों की सूची में शामिल होने वाला है, जिन्होंने भारत की वृद्धि के अनुमान में कटौती की है। भारत में जन्मी आईएमएफ प्रमुख गीता गोपीनाथ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वाशिंगटन स्थित इस संस्था ने अक्टूबर में अपना अनुमान पेश किया था और अब जनवरी में इसकी समीक्षा होने वाली है। उन्होंने इंडिया इकनॉमिक कॉन्क्लेव में यह जानकारी दी, जिसका आयोजन टाइम्स नेटवर्क ने किया। *एजेंसियां*

ज्यादा क्षेत्रीय कारोबारी समझौतों व एसईजेड में कर छूट की जरूरत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

प्रस्तावित क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) पर बातचीत से सरकार के हटने के एक महीने बाद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को और ज्यादा क्षेत्रीय कारोबारी समझौते करने की जरूरत है, जिससे विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार खुल सकें और स्थापित मूल्य शृंखलाओं का फायदा उठाया जा सके।

वाणिज्य विभाग को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि तरजीही मार्ग के माध्यम से वैश्विक कारोबार बढ़ रहा है और भारत को आगामी नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत और कारोबारी समझौतों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। सीआईआई ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के भारत सरकार के कदम का भी समर्थन किया है।

रिपोर्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में 10 साल के लिए आयकर से पूर्ण छूट, निर्यातकों के लिए सस्ते कर्ज और हाइटेक शिपमेंट में तेजी लाने का सुझाव दिया है।

बहरहाल रिपोर्ट में मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा करने की वकालत की गई है। साथ ही उद्योगों द्वारा एफटीए का लाभ लेने को लेकर अनिच्छा पर भी दुख जताया है। भारत इस समय एसोसिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ब्लॉक, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कारोबारी सौदों के लिए बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'कोरिया के साथ समझौते से हमें बाजार तक अतिरिक्त पहुंच बनाने का मौका मिलेगा और शुल्क कम होंगे, साथ ही गैर शुल्क बाधाएं भी कम होंगी।'

एफटीए साझेदारों को निर्यात के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। तीसरी दुनिया के साझेदार देशों ने उनके साथ बेहतर एफटीए किया है, जिससे भारत पिछड़ गया है। सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि अमेरिका व यूरोप से दवा कारोबार और एशियाई देशों से समुद्री उत्पाद के कारोबार को लेकर समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे कारोबार सुगम हो सके।

सीआईआई ने निर्यात बास्केट के विविधीकरण का सुझाव दिया है, जिसमें इस समय कच्चे माल, कृषि उत्पादों और कम मूल्यवर्धन वाले सामान की अहम भूमिका है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत पहले चरण में मोदी सरकार ज्यादा मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे मोबाइल फोन के निर्यात पर जोर दे रही है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के निर्यात बास्केट में हाइटेक एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 2000 और 2017 के बीच स्थिर बनी हुई है और यह सिर्फ 4.8 प्रतिशत है।

पांच साल में खुदरा ऋण दोगुना होकर 96 लाख करोड़ रु. होगा

निधि राय
मुंबई, 17 दिसंबर

भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त नरमी के कारण भले ही ऋण वृद्धि कम हो गई है लेकिन खुदरा ऋण के लिए परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। आवास, सोना, वाहन खरीदारी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋण सहित व्यक्तिगत ऋण से मिलकर खुदरा ऋण का पूल तैयार होता है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 के अंत तक खुदरा ऋण का आकार दोगुना होकर 96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है।

खुदरा ऋण की मांग में यह मजबूती आवास, कार, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, क्रेडिट कार्ड जैसे निजी खपत की मांग में वृद्धि होने, ऋण लेने की उपभोक्ताओं की इच्छा, विभिन्न उपभोक्ता आंकड़ों की बढ़ी हुई उपलब्धता, डेटा एनालिटिक्स के उपयोग में सुधार और कम लागत वाली आवास ऋणों और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) ऋणों में वृद्धि तेज करने के लिए नियामकीय पहलों से आएगी। आईसीआईसीआई बैंक के लिए तैयार किए गए अध्ययन के मुताबिक मार्च 2019 में बकाया खुदरा ऋण 48 लाख करोड़ रुपये था। माइनिंग द गोल्डन अपॉच्युनिटी इन रिटेल लोंस नाम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य और कम लागत वाले आवास ऋण के गिरवी ऋण बाजार और संपत्ति पर दिए जाने वाला ऋण वित्त वर्ष 2019 में 23.4 लाख करोड़ रुपये से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024 तक 46.1 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित कर्ज का आकार वित्त वर्ष 2019 में 5 लाख करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक 13.8 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। वहीं एमएसएमई के कर्ज का आकार वित्त वर्ष 2019 में 6.6 लाख करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक बढ़कर पांच वर्ष में 13.2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। सोने के बदले दिए जाने वाले ऋण का आकार वित्त वर्ष 19 में 2.8 लाख करोड़ से बढ़कर 3.9 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

हर गांव को इंटरनेट देने का नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन शुरू

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

सरकार ने आज नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है, जिसका मकसद 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। इस पर साझेदारों द्वारा 7 लाख करोड़ रुपये निवेश का अनुमान है।

इस मिशन को दिल्ली में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुरू किया। इसका मकसद ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच देश भर में, खासकर दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में कराना है।

इस मिशन के हिस्सा के रूप में 30 लाख रूट किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने की योजना है, जबकि कम घनत्व को 2024 तक 0.44 से बढ़ाकर 1 टॉवर प्रति हजार आबादी करना है। नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन की स्थापना राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है, जिसका वित्तपोषण युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) और सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से किया जाएगा। यूएसओएफ एक फंड है, जिसकी देखरेख संचार विभाग पिछड़े व ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच के लिए करता है।

बीएस सूडोकू 3615 | परिणाम संख्या 3614

				5	9			1
						8		2
7	1		2		8			
	8				6	2		
	4						3	
		2	4				5	
			9		1		6	5
3		4						
9			8	6				

5	2	1	6	8	4	9	3	7
4	3	6	7	9	2	5	1	8
8	7	9	3	5	1	6	2	4
2	9	3	8	1	6	7	4	5
1	4	8	5	7	9	3	6	2
6	5	7	2	4	3	1	8	9
7	6	4	1	2	5	8	9	3
9	1	5	4	3	8	2	7	6
3	8	2	9	6	7	4	5	1

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2080/2090, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670, सरसों खल 2200/2300, पामोलिन 1450/1500,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1452, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1535, फ्लेक 1472, डीएमओ 1045, टरपीन लैस बोल्ड 1562

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1170/1260, खुरपा 1140/1160,चाकू 1175/1225, रसकट 875/900, शक्कर 1180/1200, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3280, सिहोरा 3150,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4400, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2500/2600, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2145/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4600/4625,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2000/2010,

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1930/1935, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4200/4250,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7000/8000, अरहर दाल 7700/8300, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5700/6000, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5400/5500, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150, बासमती 1121 धान 2800/2850, धान (1509) 2600/2650, पीआर-11 नं. 1900/1925,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4025, हरियाणा 3950/3970, राजस्थान 3950/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2500/2550, सरसों खल 2240/2250, गेहूं चोकर (28 किलो) 600

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2365/2370, दाल उड़द छिलका 8700/10500, चना देशी 4975/5050, दाल चना 5100/5350,

करनाल
गेहूं दड़ा 2130/2140, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2800/2850, पूसा 1509 धान 2500/2575, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5150, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6700/6800, गेहूं 2130/2140,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4250/4300, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9050/9100, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 259

अकेले पड़ने का जोखिम

अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि भारत जैसी उभरती शक्तियों को अपने आसपास दोस्तों और सहयोगियों की तलाश करनी चाहिए और उनसे ऐसे रिश्ते रखने चाहिए जो दीर्घावधि में उनके आर्थिक उभार में काम आएं।

स्वाभाविक सी बात है कि आंतरिक एकजुटता बनाए रखना भी महत्त्वपूर्ण है और आंतरिक राजनीति को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह विदेश नीति के रुख और कदमों को इस तरह प्रभावित करे कि राष्ट्रीय हित को कोई लाभ न हो। दुर्भाग्य की बात है कि भारत इन बातों पर जरूरी ध्यान नहीं दे रहा है।

उदाहरण के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे व्यापक विरोध के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिनका असर हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के अधीन बांग्लादेश पड़ोस में भारत का सबसे कद्दावर साझेदार रहा है। सुरक्षा और चरमपंथ के खिलाफ दोनों का सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। हालांकि यह एकीकरण उस हद तक नहीं पहुंचा जहां तक इसे पहुंचना चाहिए था। इसके बावजूद बांग्लादेश भारत में एनआरसी को लेकर बढ़ते संकट से दूर रहना चाहता है और इस बात को समझा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक हालांकि बांग्लादेश सरकार को सार्वजनिक तौर पर यह आश्वासन दिया गया है कि एनआरसी को भारत के आंतरिक विधिक मामले के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन इस विषय पर संयुक्त आधिकारिक दस्तावेज को लेकर प्रतिरोध देखने को मिला। नागरिकता संशोधन कानून ने इस समस्या को और बढ़ा दिया क्योंकि यह कानून एक तरह से कहता है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष मुल्क नहीं है। बांग्लादेश में इसे खासा बुरा माना गया क्योंकि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की तसदीक करने से पहले वहां उसकी पहचान को लेकर काफी विभाजनकारी बहस हुई थी। इन सारे मुद्दों की अनदेखी कर दी जाती, यदि बांग्लादेश को भारत समर्थक नीति का समुचित प्रतिफल मिलता। तीस्ता जल साझेदारी से लेकर तमाम मसलों पर भारत अपने पड़ोसी मुल्क के अनुमानों पर खरा नहीं उतरा। अल्पावधि के घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेश को अलग-थलग करना समझदारी नहीं होगी।

घरेलू राजनीतिक चिंताओं ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से बाहर रहने के निर्णय में भी भूमिका निभाई होगी। आखिरकार इससे पहले के मुक्त व्यापार समझौतों पर कई प्रमुख राजनीतिक शक्तियों ने हल्ला बोला था। सत्ताधारी गठजोड़ में भी इनका विरोध हुआ था। भारत के अंतिम समय पर इससे बाहर होने के अहम कूटनयिक असर हुए होंगे और यदि इसे बदला नहीं गया तो आने वाले वर्षों और दशकों तक इसका असर पड़ सकता है। यदि ऐसा तात्कालिक राजनीतिक चिंताओं का शमन करने के लिए किया गया तो यह राष्ट्र हित को लेकर निहायत गंभीर गलत आकलन है। चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते हुए भारत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह दुनिया के सबसे बड़े उदार लोकतांत्रिक देश की अपनी उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय पूंजी को किस हद तक दांव पर लगा सकता है। कश्मीर में इंटरनेट बंद करने से लेकर तमाम अन्य कदमों ने इस पूंजी को क्षति पहुंचाई है। वृद्धि में तीव्र कमी का अर्थ यह है कि भारत बतौर साझेदार आकर्षक नहीं रह गया है। वहीं भारत में संचालित विदेशी कंपनियों के खिलाफ उठाये गये कदमों (इनमें अंतिम समय में नियम बदलकर देसी कंपनियों को लाभ पहुंचाना) के कारण विदेश में भारत के हिमायती कम हुए हैं। आशंका यही है कि एनआरसी के तहत चिह्नित लोगों के लिए बनने वाले नजरबंदी शिविरों में एक धर्म विशेष के लोग ही अधिक होंगे। इस बीच छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रतिष्ठित संस्थानों के इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है।

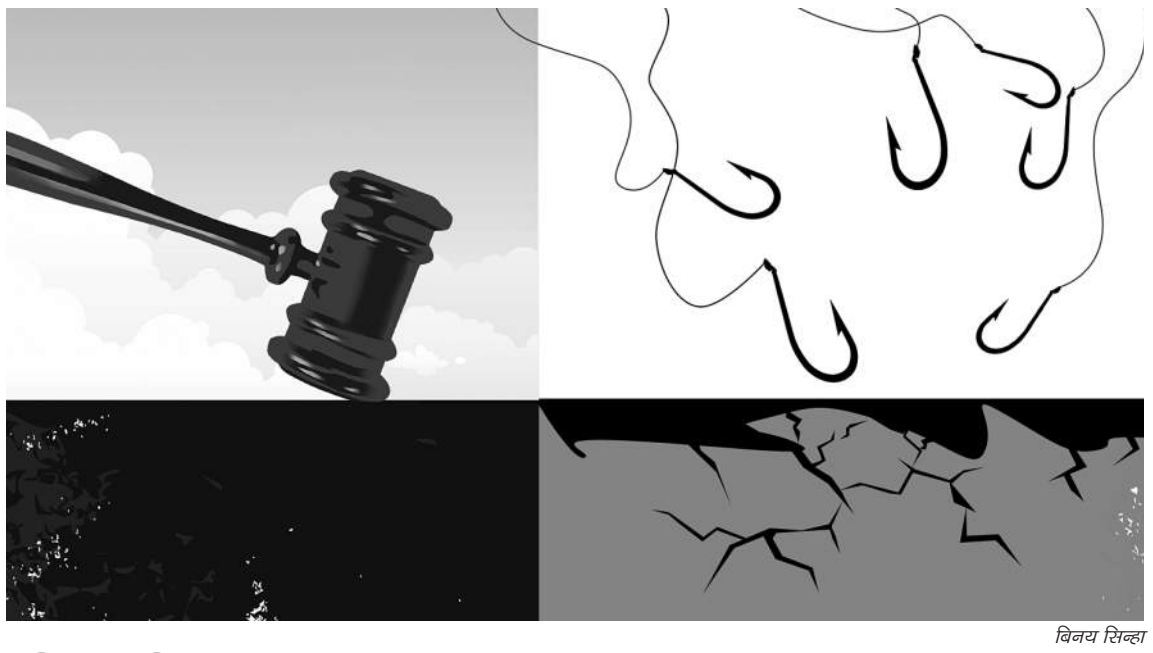

बिनय सिन्हा

विधि का शासन जरूरी बदले का भाव नहीं

विधि के शासन को प्रोत्साहित करने के बजाय हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों की हत्या ने देश के सामने एक बदनुमा नजीर पेश कर दी है। बता रहे हैं **श्याम सरन**

बलात्कार के चार संदिग्धों की एक 'मुठभेड़' में हत्या करने वाली हैदराबाद पुलिस की हो रही तारीफों के अश्लील प्रदर्शन के बीच यह सुनना आश्वस्त करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रवृत्ति को लेकर सजग किया है। उन्होंने त्वरित एवं सक्षम न्याय की जरूरत पर बल देने के साथ ही कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि न्याय कभी भी झटपट हो सकता है या उसे ऐसा होना चाहिए। न्याय को कभी भी प्रतिशोध का रूप नहीं लेना चाहिए। मेरा मत है कि न्याय अगर प्रतिशोध बन जाता है तो वह न्याय का चरित्र ही खो देता है।'

इस बयान को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बयान के बरक्स रखकर देखते हैं। राव ने दावा किया कि 'यह मुठभेड़ पूरे देश के लिए एक संदेश देती है।' उन्होंने मुठभेड़ में संदिग्धों की हत्या को सही ठहराते हुए 'तत्काल कार्रवाई के लिए बन रहे दबाव' की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेह था कि अदालती रास्ते से क्या इंसाफ मिल पाएगा? कहा गया कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। तेलंगाना सरकार ने इस गैरकानूनी कृत्य से खुद को अलग करने की बात तो दूर, सार्वजनिक रूप से इसका श्रेय लेने की भी कोशिश की। मानो मुठभेड़ में मार गिराने की इस घटना को राज्य के राजनीतिक नेतृत्व की मंजूरी हासिल थी। यह दिखावा करने की भी कोशिश नहीं की गई कि सुरक्षाबलों ने आत्मरक्षा में गोली चला दी। आपराधिक न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही गली-मोहल्लों में पुलिस गतिविधि को भी अधिक असरदार बनाना होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी कड़ी मेहनत एवं त्वरित सुधारों से बचने के लिए मनमाने ढंग से सजा देने का तरीका खतरनाक एवं निंदनीय है। आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमतर करने वाले तत्त्व भी इसकी कमजोरी के लिए जिम्मेदार हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों को 'पुलिस के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी करने, पुलिस के प्रदर्शन की समीक्षा करने, ट्रांसफर एवं पोस्टिंग और पुलिस कदाचार की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए निकाय बनाने' को कहा था। ये निर्देश अभी तक महज कागज पर ही दर्ज हैं। नेता पुलिस को संरक्षण एवं विरोधियों को निशाना बनाने के साधन के तौर पर देखते हैं। न केवल पुलिस बल्कि शासन प्रणाली के भीतर भी पेशेवर रुख एवं जनसेवा की भावना का तेजी से क्षरण हुआ है।

भारत की आबादी के अनुपात में यहां पुलिस कर्मचारियों का घनत्व बेहद कम है। स्वीकृत अनुपात प्रति एक लाख आबादी पर 181 पुलिस कर्मियों का है लेकिन वास्तविक अनुपात महज 137 है। संयुक्त राष्ट्र ने पुलिसकर्मियों एवं जनसंख्या का आदर्श मानक 222 रखा हुआ है। पुलिसकर्मियों की गुणवत्ता खराब होने के साथ गिरावट पर है। जिस तेलंगाना में जघन्य बलात्कार एवं हत्या की वारदात हुई हैं, वहां पर पुलिस के 26 फीसदी पद रिक्त हैं जबकि राष्ट्रीय दर 24 फीसदी है। महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले हमारे राजनीतिक नेता खुद ऐसे सुरक्षा घेरे में चलते हैं जिसमें सैकड़ों जवान होते हैं। इनमें कई सांसद भी शामिल हैं जिन पर हत्या एवं बलात्कार जैसे बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। क्या उन्हें इस आधार पर संक्षिप्त न्याय का विषय बनाना चाहिए कि 'भारतीय न्यायिक प्रक्रिया अनंतकाल तक चलती रहेगी?'

सार्वजनिक सुरक्षा को सुधारने और कानूनों को लागू करने के बजाय सार्वजनिक गुस्सा कम करने के लिए सभी कानूनी मानकों को परे रखते हुए जानबूझकर एवं मनमाने ढंग से संदिग्धों को मार डाला गया। अगर ऐसे आचरण को राजनीतिक एवं लोकप्रिय स्तर पर वैधता मिल जाती है तो फिर आम नागरिक के पास कोई सुरक्षा ही नहीं रह जाएगी। यह दलील दी जा रही है कि इस मामले में संदिग्धों के दोषी होने को लेकर कोई संदेह नहीं था। अगर ऐसा था तब भी उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के बगैर जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। एक खतरनाक नजीर पेश की जा रही है जो इस देश के सभी नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के मनमाने उल्लंघन की जद में ला देता है। यह उच्चतम न्यायालय के लिए स्वत:संज्ञान लेने का एकदम वाजिब मामला है ताकि मुठभेड़ हत्या में शामिल लोगों और उकसाने वाले नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया के दरवाजे पर खड़ा किया जाए।

इस तुरंत एवं कठोर 'न्याय' को सही ठहराने के लिए लोकप्रिय भावना और जन आक्रोश का हवाला दिया जाता है। यह भीड़ के शासन का दरवाजा खोल रहा है। ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि वह लोकप्रिय भावना को प्रश्रय देने के बजाय कानून के शासन को सुनिश्चित करे। चुनावी जीत राजनीतिक नेतृत्व को यह विशेषाधिकार देती है कि वह संविधान के शब्दों एवं आत्मा दोनों का ध्यान रखते हुए देश की जनता की सेवा करे। लोकप्रिय मत कानून से ऊंचा नहीं हो सकता है। सदाशयी लोगों ने भी बलात्कार की घटना से पैदा हुए गुस्से और जल्द न्याय नहीं मिलने से उपजी हताशा के चलते मुठभेड़ में की गई हत्या का समर्थन किया है। लेकिन उन्हें थोड़ा पीछे हटकर यह देखने की जरूरत है कि असल में शासन के हर पहलू में हमें नाकाम बनाने वाले लोगों को ही यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे नागरिकों को किसी कानूनी सुरक्षा-उपाय के बगैर जीवन के अधिकार से भी वंचित कर सकते हैं।

ऐसी सोच दिख रही है कि एक साथी नागरिक को आज जो झेलना पड़ रहा है वह कानून का पालन करने वाले हमारे जैसे लोगों के साथ कभी नहीं होगा। जब तक हमारे साथ ऐसा नहीं होता है तब तक यही सोचते रहते हैं। कश्मीर में अपने ही नागरिकों को आजादी से वंचित किए जाने पर तालियां बजाने की अदूरदर्शिता बेहद परेशान करती है। ऐसा हरेक मामला देश के दूसरे हिस्सों में वैसा ही काम दोहराने के लिए नजीर पेश करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नागरिकों को प्राप्त मूलभूत अधिकारों पर तर्कसंगत रोक लगाना जरूरी हो सकता है लेकिन यह कौन तय करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है और पाबंदियों के मामले में कौन सी बात तर्कसंगत है? अगर राज्य मनमाने ढंग से यह काम करता है तो ताकत के बेशर्म इस्तेमाल का दरवाजा खुल जाता है। हालिया मामलों में अदालतें यह बात मानती दिखी हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर राज्य उद्घोषणा के बगैर किसी भी तरह की पाबंदी लगा सकता है। इसके लिए अस्पष्ट आतंकी खतरों या कानून-व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका का हवाला दिया जाता है। ठोस सबूतों के आधार पर संदिग्धों को दोषी सिद्ध करना अक्सर इसका मकसद भी नहीं होता है। जांच के दौरान की प्रताड़ना और सुनवाई के दौरान कारावास में रखा जाना अपने-आप में सजा होती है।

उच्चतम न्यायालय के प्रांगण में एक बच्चे को आश्रय दे रहीं मदर इंडिया की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। यह बच्चा भारतीय गणराज्य की बाल्यावस्था को प्रतिबिंबित करता है। मदर इंडिया की गोद में कानून की एक खुली किताब भी रखी है। उस पर एक तराजू उकेरा गया है जो न्याय की समानता प्रदर्शित करता है। इसका संदेश पूरी तरह साफ है: एक युवा गणराज्य को एक गौरवान्वित एवं स्थायी लोकतंत्र बनने के लिए जरूरी है कि बच्चा कभी भी देश के कानून से न भटके। सुरक्षा का अहसास देने वाली मां की गोद तभी तक मिलेगी जब तक कानून का सम्मान एवं पालन होता रहेगा।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए करें वही जिससे बचना चाहते अन्य सभी

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

सन 2008 के पेइचिंग ओलिंपिक की शुरुआत से बमुश्किल नौ महीने पहले माइकल फेल्प्स प्रशिक्षण स्थल के बाहर फिसल गए और उनकी कलाई की हड्डी टूट गई। चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें ठीक होने में महीनों का समय लग सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया को आश्चर्य हो रहा था कि वह प्रतिस्पर्धात्मक तैराकी जारी रख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फेल्प्स और उनके प्रशिक्षक बॉब बोमैन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके बहुत जोर देने पर चिकित्सकों ने उनकी कलाई की शल्य चिकित्सा की और 10 दिन बाद यह चैंपियन खिलाड़ी वापस तैराकी कर रहा था।

उसके बाद की बातें इतिहास बन चुकी हैं। फेल्प्स ने आठ स्वर्ण पदक जीते। उनकी इस चकित करने वाली सफलता के पीछे बहुत कड़ी मेहनत छिपी थी। फेल्प्स ने बिना अपने बाजुओं की मदद लिए तैरना शुरू किया क्योंकि फ्रैक्चर के कारण वह अपने शरीर के ताकतवर ऊपरी हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी टांगों की कमजोरी पर भी ध्यान देना पड़ा। आखिरकार फेल्प्स पेइचिंग ओलिंपिक में अपनी नई ताकतवर किक की बदौलत कई प्रतिस्पर्धाएं जीतने में कामयाब रहे। यह आकस्मिक योजना के लिए सटीक सबक है। आप और आपकी टीम के सदस्यों को यह सोचना चाहिए कि यदि चीजें सही ढंग से न हो रही हों तो क्या किया जाना चाहिए।

सन 2000 में सिडनी ओलिंपिक के फाइनल में पांचवें स्थान पर आने के बाद 15 वर्षीय फेल्प्स ने कहा था कि मेडल पोडियम पर नहीं पहुंच पाने को उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया। वह अगले दिन भी तैराकी के लिए पूल में उतर गए। छह महीने बाद उन्होंने पहला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।

इससे साबित होता है कि अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी सफलता का कोई शॉर्ट कट नहीं होता। फेल्प्स सप्ताह में सातों दिन रोज छह घंटे जमकर तैराकी करते। यह सिलसिला अगले करीब दो दशकों तक पूरे वर्ष चलता रहा।

अन्य तैराक जहां सप्ताह में एक दिन अवकाश लेते, वहीं अपनी इस आदत की वजह से फेल्प्स को हर वर्ष 52 दिन का अतिरिक्त समय प्रैक्टिस के लिए मिलता। फेल्प्स ने पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा था, 'यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको वह करना हो जो अन्य लोग नहीं करना चाहते।'

समिट में उनकी बातें नेतृत्व के बारे में अहम सबक देती हैं। उनसे पता चलता है कि चैंपियन कैसे बनते हैं और कैसे वे विपरीत परिस्थितियों से निपटते हुए उसे अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त का जरिया बनाते हैं। रोजमर्रा की कड़ी मेहनत के अलावा कुछ अन्य सबक भी हैं जो विभिन्न मंचों पर फेल्प्स के वक्तव्यों से निकले हैं:

1. सफलता के लिए तैयार रहें: फेल्प्स ने दिखाया कि क्यों असहजता के साथ सहज होना जरूरी है। ऐसे में किसी भी नेतृत्वकर्ता के प्रशिक्षण में हर तरह की आकस्मिकता की तैयारी जरूरी है। उस दृष्टि से देखा जाए तो तैराकी के दौरान होने वाली घटनाएं उन्हें भयभीत नहीं कर सकीं, न ही उन्हें असहज कर सकीं। संक्षेप में कहें तो लक्ष्य तय करें, यह पता लगाएं कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना होगा और इसके बाद पूरी शिद्दत से उसे हासिल करने में जुट जाएं।

2. कभी हार न मानें: फेल्प्स को अपने जीवन के चमकदार दिनों में कई झटकों का सामना करना पड़ा। पेइचिंग ओलिंपिक से ऐन पहले कलाई की हड्डी टूटना भी ऐसी ही एक घटना थी। परंतु वह हर बार वापसी करने में कामयाब रहे। जरा इस पर विचार कीजिये: फेल्प्स के करियर के बेहतरीन दिनों में एक तस्वीर ने उनके जीवन में उथल-पुथल मचा दी। यह एक कॉलेज पार्टी की तस्वीर थी जिसमें वह मारिजुआना का सेवन करते हुए दिख रहे थे। उनका मजाक उड़ाया गया, बड़े-बड़े अनुबंध उनके हाथ से निकल गए। उनके तैराकी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वह इतने अवसाद में चले गए कि बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन उन्होंने वही किया जो चैंपियन खिलाड़ी करते हैं: उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और सुधार किया। इसके बाद वह अपना खोया हुआ जादू दोबारा पाने में जुट गए। सार्वजनिक आयोजनों में फेल्प्स ने ब्रांड प्रतिष्ठा के बचाव के बारे में बात की और कहा कि इसे हर कीमत पर बचाना चाहिए क्योंकि एक मजबूत ब्रांड तैयार करने में कई वर्ष लगते हैं। परंतु 60 सेकंड की गलती से आप सब कुछ गंवा सकते हैं।

3. स्पष्ट लक्ष्य तय करें: फेल्प्स ने ऐसा ही किया क्योंकि उन्होंने पाया कि कागज पर लक्ष्य को लिखकर रखने और उसे बार-बार देखने से मदद मिलती है। खासतौर पर एक मुश्किल दिन बिताने के बाद। पहले वह जहां अपनी अगली प्रतियोगिता या तैयारी के बारे में सोचते थे, वहीं बाद में उन्होंने 5, 10 और यहां तक कि 20 साल आगे के लक्ष्य तय करने शुरू किए। एक नेतृत्वकर्ता के लिए दूरगामी सोच बहुत मायने रखती है।

4. हर सफलता के बाद मानक ऊंचा करें: अपने लक्ष्य लिखकर रखना और खुद को उनके बारे में याद दिलाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जैसे फेल्प्स आठ वर्ष की उम्र में तय करने लगे थे। फेल्प्स ने कहा कि वह तमगे जीतने के पीछे नहीं थे, वह समय के पीछे थे। उन्हें पता था कि उनके प्रतिस्पर्धी तय दूरी की तैराकी में कितना समय ले रहे हैं। वह अपने प्रतिस्पर्धियों को इतने अच्छे से जानते थे जितना शायद वे खुद को भी न जानते हों। उनको पता था कि सबको पीछे छोड़ने के लिए उन्हें क्या समय निकालना होगा। जाहिर है उन्होंने कभी अपनी तुलना किसी और से नहीं की और हमेशा अपने पुराने प्रदर्शन को पछाड़ने की कोशिश की।

इन बातों से साफ होता है कि सफलता का रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है।

कानाफूसी

आंतरिक संघर्ष

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) आगामी गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। यह सम्मेलन केंद्र सरकार की निजीकरण, विनिवेश, सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने, बैंकिंग और बीमा कंपनियों में विलय तथा रेलवे तथा रक्षा उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। बीएमएस ने कहा है कि वह यह मांग करेगा कि सरकार वेतन भत्तों पर नए सिरे से बातचीत करे, वेतन-भत्तों का बकाया निपटाये, कमजोर सरकारी उपक्रमों की मदद करे और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन संशोधित करे। ध्यान रहे बीएमएस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखता है।

कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष?

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने एक वर्ष पूरा हो चुका है लेकिन पार्टी अब तक प्रदेश इकाई के लिए अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है। मुख्यमंत्री कमल नाथ प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के रूप में दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह बार-बार कह चुके हैं कि वह प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सत्ता के कई ध्रुव हैं इसलिए पार्टी नेतृत्व ने पहले यथास्थिति बरकरार रखने में ही भलाई समझी। अब जबकि प्रदेश सरकार सुरक्षित है, पार्टी ने राज्य इकाई के अध्यक्ष की तलाश फिर से शुरू कर दी है। इस पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं वे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह (पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र), उमंग सिंघार (पार्टी का आदिवासी चेहरा) और बाला बच्चन (राज्य के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी)।

कमल नाथ

आपका पक्ष

प्याज की कीमतों को काबू करे सरकार

अगर देश में कोई भी खाने की चीज जो गरीब तबके के लिए रोजाना इस्तेमाल में होती हो वह महंगी हो जाए तो सरकार को उसकी कीमत कम करने के उपाय प्राथमिकता के आधार पर करने चाहिए। विकास के वादे और दावे तब तक खोखले माने जा सकते हैं, जब तक देश में पैदा होने वाली चीजें महंगी हों। सरकार को प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए पहल करनी चाहिए क्योंकि कुछ जगह इसकी कीमतें 100 रुपये किलो से अधिक पहुंच गई हैं। वैसे प्याज की कीमतें इससे पहले भी बढ़ती थी और इस पर खूब राजनीति भी होती थी। प्याज पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े जाते रहे हैं। लेकिन महंगाई के समाधान के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने आज तक गंभीरता नहीं दिखाई है। यह कोई नई बात नहीं है कि प्याज के दाम अभी इतने बढ़े हों। इससे पहले भी हर राजनीतिक पार्टी की सरकार चाहे वह कांग्रेस की हो या भाजपा की, प्याज के दाम आसमान पर चढ़े हैं। वर्तमान सरकार अगर प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने में असफल रही तो यही प्याज चुनाव के समय नेताओं की आंखों से आंसू निकाल सकता है। इसलिए सरकार को प्याज की कीमतें फौरन नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। कृषि विशेषज्ञों को चाहिए कि वह ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे देश के हर राज्य में प्याज की पैदावार बढ़े। सिर्फ नाशिक के प्याज की पैदावार पर ही देश निर्भर नहीं रहे। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार काफी तर्क दे सकती है लेकिन जो मुख्य कारण हैं उनमें कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। प्याज के बढ़ते दाम के लिए सरकार की नीतियों में सुधार की जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

देश के हर राज्य में प्याज की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए

बुजुर्गों की देखभाल के लिए कानून

हम अक्सर देश के भविष्य की बात करते हैं लेकिन देश के भविष्य को जिन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा है उन्हें भूल जाते हैं। हम बुजुर्गों की बात कभी कभार ही करते हैं जब मीडिया में किसी बुजुर्ग के प्रताड़ित होने की खबर आती है। देश, समाज और वर्तमान के निर्माण में कल अर्थात बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन्हीं बुजुर्गों की हम उपेक्षा कर देते हैं। आज न्यूक्लियर परिवार में बुजुर्गों का योगदान खत्म होता जा रहा है। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें अपने ही बच्चे घर से निकाल देते हैं या फिर उनकी देखभाल नहीं करते हैं। हाल में संसद में वरिष्ठ नागरिकों तथा माता-पिता के भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने तथा उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में पुत्रवधू और दामाद को बालक की परिभाषा में लाने की बात कही गई है। अगर यह कानून बनता है तो बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय को कम किया जा सकेगा। बेटे, बहू, बेटी तथा दामाद पर भी अपने अभिभावकों की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

दीपिका कुमारी, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 18 दिसंबर 2019 बुधवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

दो महीने में खाद्य तेल आयात 50 प्रतिशत फिसला

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 17 दिसंबर

पिछले दो महीने के दौरान देश के रिफाइंड खाद्य तेल आयात में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट आई है। प्रसंस्करण उद्योग की ओर से अनुरोध किए जाने के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा पांच प्रतिशत का संरक्षण शुल्क लगाए जाने के बाद ऐसा हुआ है।

उद्योग के शीर्ष संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (सीईए) द्वारा एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि नवंबर में आरबीडी (रिफाइंड, ब्लिच्ड और डि-ओडोराइज्ड) तेल आयात 53 प्रतिशत गिरकर 1,23,000 टन रह गया, जबकि सितंबर में 2,64,000 टन आयात किया गया था। मुख्य रूप से मलेशिया से आयात किए जाने वाले आरबीडी पामोलिन पर 26 अगस्त को संरक्षण शुल्क लगाया गया था। जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने पर मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा की गई आलोचना के बाद ऐसा किया गया था।

भारत सालाना 1.55 करोड़ टन आयात की जरूरत पूरी करने के लिए तकरीबन 90 लाख टन कच्चे पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से और 30 लाख टन आयात अर्जेंटीना से करता है। सालाना घरेलू मांग करीब 2.5 करोड़ टन रहती है।

सीईए के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि आरबीडी पामोलिन आयात में इस गिरावट का एकमात्र कारण मलेशिया से आयात पर संरक्षण शुल्क लगाया जाना है। आगे चलकर भी इसका आयात नरम रहने के आसार हैं। रिफाइंड तेल आयात में इस गिरावट की वजह से नवंबर में कुल वनस्पति तेल आयात गिरकर 6,69,363 टन रह गया, जबकि सितंबर में आयात 8,80,346 टन हुआ था।

किसानों को लाभ की उम्मीद

खरीफ की कम उपज और रबी की अधिक उत्पादकता से फायदा

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 17 दिसंबर

खरीफ की कम उपज और रबी फसल की अधिक उत्पादकता के कारण कृषि जिंसों की कुल कीमतों में इजाफा होने की वजह से फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई से जून) के दौरान किसानों को सात से नौ प्रतिशत ज्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। क्रिसिल के अध्ययन में यह बात सामने आई है। फसल वर्ष 2018-19 में किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत अधिक लाभ अर्जित किया था। वर्ष 2017-18 के दौरान जोरदार फसल होने के बाद मंडी में कम दामों के कारण प्रति हेक्टेयर लाभ में गिरावट आई थी।

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है इसलिए कृषि मुनाफे में होने वाले लगातार इजाफे से कृषि जिंसों के उत्पादकों को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। कृषि मुनाफे में इस निरंतर वृद्धि से खेती छोड़ चुके किसानों को भी फिर से खेती की ओर लौटने में मदद मिलेगी।

क्रिसिल की निदेशक हेतल गांधी ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर के दौरान असाधारण रूप से हुई भारी बारिश से खरीफ फसल उत्पादन में चार से छह प्रतिशत तक की गिरावट रहेगी। दूसरी तरफ सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक रहने वाले मॉनसून ने जलाशयों को लबालब कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप रबी फसल की उत्पादकता बढ़ने के आसार हैं जिससे उपज में सात से आठ प्रतिशत इजाफा होने की संभावना है। एक ओर खरीफ खाद्यान्न की बाजार आपूर्ति कम रहने से मंडी में दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे, दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गेहूं (रबी उत्पादन में जिसका योगदान 50 प्रतिशत से अधिक रहता है) के लिए सरकार के प्रोत्साहन से रबी फसल के दामों में इजाफे को मदद मिलने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति हेक्टेयर कुल कृषि मुनाफा बढ़ जाएगा।

- **फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई से जून) के दौरान किसानों को 7 से 9 प्रतिशत ज्यादा लाभ मिलने के आसार**
- **फसल वर्ष 2018-19 में किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत अधिक लाभ कमाया था**
- **सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है**
- **कृषि मुनाफे में होने वाले लगातार इजाफे से कृषि जिंसों के उत्पादकों को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी**

30 जून को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से 28 प्रतिशत कम और 30 जुलाई को सामान्य से नौ प्रतिशत कम रहा जिससे इस साल खरीफ फसल की बुआई में देरी हुई। हालांकि अगस्त और सितंबर में तेज सुधार के परिणामस्वरूप 1 जून से 30 सितंबर के बीच मॉनसून सीजन सामान्य से 10 प्रतिशत से अधिक हो गया।

हालांकि मॉनसून की प्रगति की वजह से बुआई की रफ्तार ने जोर पकड़ा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में सूखा जारी रहा। दूसरी ओर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में इस वर्ष अधिक बारिश और बाढ़ के कारण फसल को नुकसान पहुंचा।

चीनी निर्यात 50 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के आसार

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू हुए नए सत्र में 20 लाख टन निर्यात के लिए सौदा किया

भारत इस साल चीनी निर्यात का अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आकर्षक वैश्विक कीमतों के कारण दूसरे देशों को की जाने वाली बिक्री में उछाल आई है। व्यापार और उद्योग के अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। भारत में चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू हुए नए सत्र में 20 लाख टन निर्यात के लिए सौदा किया है। इससे उम्मीद है कि 2019-20 के सत्र में भारत वैश्विक बाजार में कम से कम 50 लाख टन चीनी की बिक्री करेगा जो पिछले वर्ष से करीब एक-तिहाई अधिक है। एक वैश्विक कारोबारी कंपनी की नई दिल्ली स्थित भारतीय इकाई के व्यापारी ने कहा, 'मौजूदा रुझान को देखते हुए मैं आपको काफी भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस साल हम कम से कम 50 लाख टन चीनी निर्यात करेंगे।'

भारत 50 लाख टन चीनी निर्यात के साथ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देगा। व्यापार एवं उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक 2007-08 में भारत ने सर्वाधिक 49.6 लाख टन चीनी निर्यात किया था। बिक्री में यह उछाल वैश्विक कीमतों में आई मजबूती, भारतीय रुपये में कमजोरी और सरकार की ओर से दी जा रही छूट के कारण है जिससे निर्यात आकर्षक हो गया है। एमईआईआर कमोडिटीज इंडिया के प्रबंध निदेशक राहिल शेख ने कहा, 'पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल सत्र की शुरुआत से ही निर्यात में तेजी रही है जिसकी वजह चीनी की कीमतों आई मजबूती है।'

भारत से होने वाले निर्यात में तीव्र बढ़ोतरी का असर न्यूयॉर्क और लंदन की बेंचमार्क कीमतों पर पड़ सकता है और इससे प्रतिस्पर्धी ब्राजील, थाइलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के शीर्ष चीनी आपूर्तिकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। भारत से अधिक मात्रा में चीनी निर्यात होने के कारण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में व्यापार संबंधी विवाद गहरा सकते हैं। ब्राजील पहले ही कह चुका है कि चीनी निर्यात के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही छूट डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक नहीं है और इससे वैश्विक बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा को धक्का लगेगा। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने डब्ल्यूटीओ में भारत सरकार की ओर से दी जा रही छूट पर प्रश्न खड़ा किया है।

अतिरिक्त चीनी आपूर्ति को लेकर परेशान भारत ने 2019-20 के दौरान निर्यात पर 10,448 रुपये प्रति टन की छूट देने को मंजूरी दी है। सरकार के इसी कदम से उत्साहित होकर मिलों ने इस साल चीनी निर्यात का सौदा पहले ही कर लिया है। व्यापारियों ने औसतन 300 डॉलर प्रति टन की दर से कच्ची चीनी और 330 डॉलर प्रति टन की दर से सफेद चीनी निर्यात के लिए समझौता किया है। यह जानकारी इन सौदों में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहे तीन विक्रेताओं ने दी। इस साल अब तक 20 लाख टन निर्यात के लिए हुए समझौतों के उलट 2018-19 सत्र के पहले तीन महीनों में भारतीय चीनी मिलें केवल लगभग 8,50,000 टन चीनी की ही बिक्री कर पाई हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 17	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,763.0	0.9	1,901.9	-3.2
Copper	6,155.5	6.8	6,452.5	4.6
Nickel	14,085.0	-17.1	14,652.0	-17.5
Lead	1,873.5	-8.9	2,226.0	8.0
Tin	17,180.0	2.8	18,033.2	-0.4
Zinc	2,269.0	-3.2	2,606.4	0.6
Gold ($/ounce)	1,478.9*	-1.5	1,663.4	1.5
Silver ($/ounce)	17.1*	-5.3	19.4	-2.9
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.3*	4.3	65.8	-2.3
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-13.1	2.3	-12.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	188.9	12.4	301.1	6.4
Maize	184.7*	1.7	328.8	12.7
Sugar	352.0*	9.7	484.5	-0.1
Palm oil	707.5	29.8	1,132.7	30.1
Rubber	1,613.1*	0.5	1,859.7	0.4
Coffee Robusta	1,423.0*	9.8	1,894.9	-7.5
Cotton	1,471.4	11.0	1,583.7	-1.3

* As on Dec 17, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0 & 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	35.6	12395
Oil and Oilseeds	272.5	75557
Spices	2.0	16
Metal(Dec 16)		
Metal- non ferrous	4793.6	61939
Metal- precious	8480.6	439
Oil and gas(Dec 16)		
Gas	2208.4	40293
Oil	9268.4	3170

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	120.1	104682
Grains	218.2	95460
Oil and Oilseeds	822.3	488800
Others	112.2	66910
Pulses	66.9	51300
Spices	32.4	31989

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3271.9	3.9
Natural Gas (Dec 26)	168.0	3.2
Silver (Mar 05)	44493.0	0.8
Silver Micro (Feb 28)	44517.0	0.8
Silver Mini (Feb 28)	44513.0	0.8
Aluminium Mini (Dec 31)	134.0	0.8
Aluminium (Dec 31)	134.0	0.8
Crude Oil (Dec 18)	4272.0	0.7
Losers (* % Change)		
Cotton (Dec 31)	19110.0	-0.7
Mentha Oil (Dec 31)	1307.3	-0.7
Kapas (Apr 30)	1099.5	-0.3
Crude Palm Oil (Dec 31)	731.1	-0.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7370.0	2.2
Guar Seed 10 (Dec 20)	4044.0	1.3
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4560.0	1.2
Soyabean Indore (Dec 20)	4256.0	1.1
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	877.8	1.1
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6182.0	1.0
Chana-Bikaner (Dec 20)	4419.0	0.9
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2059.0	0.2
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4254.0	0.2
Losers (* % Change)		
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1097.5	-0.6
Coriander-Kota (Dec 20)	6950.0	-0.4
Jeera Unjha (Jan 20)	15810.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3271.9	5.5
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19110.0	2.1
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	1.4
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3854.0	1.3
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44517.0	0.7
Silver Ahm (Mar 05)	44493.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1307.3	-7.6
Aluminium Mum (Dec 31)	134.0	-2.3
Alumini-Mumbai (Dec 31)	134.0	-2.3
Copper Mum (Dec 31)	443.0	-2.3
Nickel Mumbai (Dec 31)	1034.1	-1.1
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	182.4	-1.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6182.0	2.5
Barley Jaipur (Dec 20)	2129.0	0.2
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3202.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Jan 20)	15810.0	-3.3
Moong-Merta City (Dec 20)	6682.0	-2.5
Soy Bean Indore (Dec 20)	4256.0	-1.7
Maize-Sangli (Dec 20)	2030.0	-1.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7370.0	-0.8
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	739.7	-0.8
Coriander-Kota (Dec 20)	6950.0	-0.3
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18690.0	-0.1

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98.......(98)
Aluminium ingots /kg	135.......(135)
Brass sheet cutting /kg	321.......(319)
Brass utensil scraps/kg	306.......(303)
Copper heavy scrap /kg	425.......(422)
Copper utensil scraps/kg	400.......(398)
Copper wire bar /kg	458.......(456)
Lead ingots /kg	158.......(157)
Nickel Cathodes /kg	1040.......(1040)
Tin slabs /kg	1280.......(1275)
Zinc slabs /kg	185.......(184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10742.......(10742)
DCH - 32 /Qtl	11276.......(11473)
Jaydhar /Qtl	10067.......(10067)
Shankar- 6 /Qtl	11079.......(11276)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	910.......(910)
Castor Comm /10kg	900.......(900)
Ricebran oil/10kg	760.......(760)
Groundnut oil /10kg	1090.......(1065)
Linseed oil /10kg	895.......(875)
Karanji /10kg	780.......(780)
Palm oil /10kg	808.......(806)
Sunflower exp ref /10kg	868.......(865)
Sunflower oil exp /10kg	825.......(815)
Sesame /10kg	-(-)
Soyabean ref / 10kg	865.......(860)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3282-3596 ....(3302-3596)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.24.......(60.21)
Brent Crude (UK)	67.06 ....(67.11)
Brent Crude (WTI)	60.21.......(60.21)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu (2.34)	.......2.32
Furnace/ 180 Cst &/bbl	275.6 ....(264.91)
Naptha spot /Rs/MT	45170.......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.......(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37959.......(37882)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38112.......(38034)
Silver.999/ kg	44275.......(44165)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18672.45	18701.55
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.25	137.15
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2010.00	2050.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2127.50	2124.25
Brass-Jamnagar (M)	1 K	312.50	312.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3067.00	3067.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4324.40	4344.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4247.50	4300.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4300.00	4326.25
Chana Delhi (N)	1 Q	4504.15	4514.05
Chana-Akola (N)	X	4300.00	4400.00
Coriander-Gondal (N)	X	6650.00	6700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6942.20	7013.75
Coriander-Kota (N)	1 Q	7000.00	6973.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2096.20	2103.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2061.30	2089.30
Cotton-Kadi (N)	1 B	18628.60	18644.55
CPO-Kandla (M)	10 K	731.40	735.20
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	737.95	745.45
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	880.10	884.00
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1528.55	1529.50
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3433.75	3435.60
Gold Ahm (M)	10 G	37891.00	37936.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30435.00	30471.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3803.00	3806.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7269.05	7431.25
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3931.15	4025.40
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3825.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1164.35	1192.35
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16850.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16354.55	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1026.35	1032.90
Kapas-Rajkot (N)	X	1023.30	1028.60
Lead Mum (M)	1 K	153.30	153.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2043.15	2060.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2331.60	2370.00
Maize-Erode (N)	X	2088.00	2086.80
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2225.00	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	2061.35	2062.75
Moong-Merta City (N)	1 Q	6820.00	6851.55
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4746.00	4746.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1030.80	1045.60
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3195.00	3180.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	354.40	354.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35500.00	35666.65
Rape mustards-Patan (I)	20 K	822.00	820.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2040.00	2043.15
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	800.00	804.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	865.10	875.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	861.70	869.05
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	876.00	885.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13250.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13258.00	13258.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44128.00	44199.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4270.00	4328.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4191.50	4242.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4292.50	4380.90
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4343.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34538.00	35000.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	860.50	873.80
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27910.00	28090.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28900.00	29090.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25820.00	26270.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3304.60	3302.85
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3293.75	3275.90
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3438.10	3435.70
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3133.50	3130.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6030.00	6029.15
Wheat Delhi (N)	1 Q	2259.15	2268.15
Wheat Kota (N)	1 Q	2135.00	2138.15
Wheat New Indore (N)	1 Q	2225.00	2212.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2075.00	2085.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2180.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4850.00	4887.30
Zinc Mumbai (M)	1 K	182.45	184.25

* as on Dec 16, 19
(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (मंगलवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19180, 19190, 19100, 19110	1854	287	7028
Jan 31	19380, 19400, 19320, 19320	1212	204	4332
Feb 28	19500, 19500, 19500, 19500	13	3	344
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2072, 2072, 2045, 2059	890	19	7770
Jan 20	2073, 2095, 2054, 2061	36220	2604	60330
Feb 20	2099, 2114, 2076, 2082	10380	835	29180
Mar 20	2107, 2130, 2100, 2122	760	75	2980
Apr 20	2130, 2130, 2130, 2130	10	1	110
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1100, 1100.5, 1097.5, 1099.5	144	22	656
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1102, 1103, 1097, 1097.5	899	346	4312
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4024, 4044, 4024, 4044	4735	72	1465
Jan 20	4060, 4118, 4054, 4076	45630	4459	83205
Feb 20	4094, 4154, 4094, 4114	3055	435	6780
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4240, 4256, 4240, 4254	1400	89	3080
Jan 20	4286, 4294, 4260, 4284	4520	416	30015
Feb 20	4280, 4300, 4278, 4296	325	32	4210
Mar 20	4274, 4278, 4274, 4276	150	19	4485
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	738.9, 740.5, 730.3, 731.1	11500	822	23900
Jan 31	739.5, 742, 731.6, 732.3	17870	1019	45810
Feb 28	739, 741, 730, 730.6	3300	213	5500
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1313, 1321.9, 1305.7, 1307.3	203.4	509	259.92
Jan 31	1323.5, 1330.9, 1315.9, 1317	39.24	102	87.12
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4563, 4563, 4560, 4560	380	14	2280
Jan 20	4571, 4606, 4557, 4563	21670	1382	19600
Feb 20	4500, 4545, 4494, 4515	590	50	1500
Apr 20	4421, 4434, 4398, 4408	1100	83	3040
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	876.4, 878.8, 873, 877.8	1465	135	7405
Jan 20	881, 886.4, 880.8, 883	23990	2600	49090
Feb 20	874, 877, 872.4, 874.6	6650	622	30540
Mar 20	868, 870, 866.6, 868	395	34	445
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4230, 4270, 4230, 4256	3525	522	2505
Jan 20	4252, 4308, 4248, 4296	64545	6727	169540
Feb 20	4298, 4340, 4278, 4328	18995	2531	120850
Mar 20	4326, 4374, 4312, 4366	5185	716	37615
Apr 20	4398, 4410, 4398, 4402	900	137	2550
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7247, 7370, 7247, 7370	140	14	505
Jan 20	7340, 7449, 7326, 7381	12100	1925	59920
Feb 20	7440, 7548, 7440, 7483	2880	444	6375
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4410, 4430, 4410, 4419	510	41	2070
Jan 20	4382, 4435, 4377, 4429	13910	1080	45410
Mar 20	4349, 4384, 4345, 4376	610	54	3210
Apr 20	4341, 4360, 4341, 4360	110	2	550
May 20	4350, 4350, 4350, 4350	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3243.4, 3274.9, 3194.5, 3271.9	4.3	37	11.9
Feb 14	3094.9, 3138, 3080, 3113.5	1.9	19	3.2
Mar 13	2970, 2970, 2970, 2970	0.2	2	0.6
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7000, 7000, 6950, 6950	140	12	3190
Jan 20	6562, 6582, 6450, 6490	1750	151	8830
Apr 20	6870, 6900, 6807, 6855	230	22	4340
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15895, 15935, 15770, 15810	444	143	2679
Mar 20	15650, 15650, 15530, 15610	66	22	252
Apr 20	15500, 15500, 15445, 15450	12	4	33
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6150, 6200, 6150, 6182	200	24	2985
Mar 20	6152, 6238, 6152, 6206	1085	188	7210
Apr 20	6072, 6124, 6050, 6084	370	71	2455

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.9, 134.35, 133.2, 133.5	5795	937	8065
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.9, 134.35, 133.2, 133.5	2258	1771	2934
Jan 31	134.1, 134.75, 133.9, 134.15	325	257	827
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.6, 444.4, 442.35, 443.7	13190	4404	15220
Jan 31	447.6, 449.2, 447.5, 448.65	1035	382	2640
Feb 28	452.75, 453.2, 452.3, 452.85	15	6	47.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 153.05, 152.5, 152.7	8935	1401	7045
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 153.05, 152.5, 152.8	2579	2090	2564
Jan 31	152, 152.4, 151.9, 152.05	261	227	1672
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1032.6, 1038.6, 1031.4, 1034.6	8581.5	5119	3069
Jan 31	1032.6, 1034.5, 1029, 1029.8	129	84	471
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.6, 183.9, 182.6, 183.4	15565	2576	15100
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.35, 183.6, 182.35, 183.15	5185	3988	5965
Jan 31	179.6, 181.9, 179.6, 181.5	1732	960	7782
Feb 28	181.7, 181.7, 181.5, 181.6	2	2	26
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37869, 37980, 37845, 37969	6.13	4934	16.25
Apr 03	37936, 38044, 37899, 38035	0.29	216	3.32
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30491, 30550, 30491, 30526	0	84	0
Jan 31	30430, 30450, 30403, 30439	0	23	0
Feb 28	30498, 30498, 30498, 30498	0	1	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37863, 37975, 37850, 37963	0.58	4838	0.88
Feb 05	37863, 37988, 37855, 37973	0.13	1152	0.27
Mar 05	37951, 38015, 37949, 37998	0	17	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3853, 3857, 3851, 3856	0	304	0.01
Jan 31	3838, 3845, 3836, 3841	0	120	0
Mar 31	3800, 3800, 3800, 3800	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44444, 44620, 44424, 44576	218.97	6042	376.92
May 05	45058, 45093, 44957, 45029	0.51	17	6.27
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44474, 44640, 44453, 44589	16.95	11714	30.16
Apr 30	44990, 45120, 44943, 45068	0.99	619	1.82
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44517, 44645, 44447, 44588	62.01	9826	54.52
Apr 30	44948, 45109, 44944, 45091	0.71	131	2.14

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	167.6, 167.6, 164.3, 165.2	41575mb	18177	30311mb
Jan 28	166.7, 167.2, 164.4, 165.1	3974mb	2093	12804mb
Feb 25	163.8, 163.8, 161.3, 161.8	638mb	431	3459mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4263, 4283, 4256, 4277	6493bl	32902	3129bl
Jan 17	4271, 4285, 4263, 4281	663bl	4067	951bl
Feb 19	4288, 4288, 4265, 4278	6bl	36	6bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4267, 4284, 4256, 4277	1241bl	50412	700bl

सायं सत्र (सोमवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19260, 19260, 19150, 19210	2262	415	7100
Jan 31	19390, 19470, 19350, 19420	2011	361	4243
Feb 28	19590, 19600, 19590, 19600	47	8	344
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1094, 1105, 1092, 1101.5	380	81	636
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1093, 1105, 1091, 1103	1371	839	4241
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	727.4, 734.9, 721, 733.6	15270	1099	24680
Jan 31	728.5, 737.5, 721.1, 735.8	16440	1081	47370
Feb 28	723.8, 737, 720.9, 735.9	1150	89	6020
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	872, 873.4, 865, 867.4	4080	373	8050
Jan 20	871, 879.8, 864, 876.6	35175	3664	46385
Feb 20	865.2, 870.8, 853.4, 868	10815	802	27850
Mar 20	853.6, 864.6, 853.6, 860.6	25	5	85

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.95, 134.35, 132.85, 133.95	8760	1392	7605
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.9, 134.3, 132.9, 133.95	4122	3055	2630
Jan 31	133.6, 134.55, 133.5, 134.2	370	305	733
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441.15, 443.45, 440.9, 442.95	26612.5	8711	13005
Jan 31	443.35, 448.4, 443.3, 448	1335	488	2235
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.1, 153.15, 151.9, 152.35	18105	2915	5730
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.3, 153.15, 152.05, 152.4	6980	5466	2159
Jan 31	151.75, 152.45, 151.45, 151.8	1020	686	1600
Feb 28	152.4, 152.4, 152.4, 152.4	5	2	5
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1030, 1036.5, 1023, 1034.1	18715.5	11095	1614
Jan 31	1019.4, 1032.8, 1011.8, 1031.1	535.5	340	462
Feb 28	1025.4, 1025.4, 1025.4, 1025.4	1.5	1	3
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.05, 182.9, 181.65, 182.6	39720	6427	11585
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182, 182.6, 181.6, 182.4	13220	10277	5105
Jan 31	180.15, 180.75, 179.4, 180.6	1947	1430	7404
Feb 28	180.35, 180.35, 179.5, 179.85	20	10	26
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37725, 37967, 37725, 37871	11.17	9532	15.37
Apr 03	37850, 38029, 37815, 37952	0.56	482	3.1
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30485, 30540, 30467, 30512	0	230	0
Jan 31	30399, 30470, 30381, 30430	0	95	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37740, 37948, 37735, 37873	1.3	11172	0.78
Feb 05	37755, 37967, 37755, 37877	0.27	2332	0.25
Mar 05	37747, 37980, 37747, 37882	0.01	81	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3854, 3865, 3845, 3854	0	772	0.01
Jan 31	3829, 3843, 3829, 3837	0	276	0
Feb 28	3826, 3839, 3820, 3824	0	6	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44132, 44573, 44108, 44493	553.5	14703	338.22
May 05	44671, 45000, 44671, 44931	1.47	49	6.06
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44250, 44585, 44100, 44517	48.98	33976	27.4
Apr 30	44637, 45050, 44632, 44998	2.22	1773	1.68
Jun 30	45100, 45100, 45100, 45100	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44186, 44595, 44134, 44513	166.07	26156	43.78
Apr 30	44642, 45061, 44637, 44998	2.25	424	1.97

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	161.4, 168.9, 161.1, 168	120844mb	52712	25215mb
Jan 28	163.6, 167.8, 162.5, 167.2	10523mb	5367	11888mb
Feb 25	161, 164.5, 160.3, 164	1838mb	1258	3190mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4236, 4279, 4230, 4272	16777bl	86993	1985bl
Jan 17	4236, 4282, 4233, 4276	1220bl	7788	721bl
Feb 19	4260, 4275, 4241, 4273	2bl	22	2bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4233, 4279, 4229, 4272	3749bl	145304	462bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

'जामिया मामले में हाईकोर्ट जाएं'

देश के शीर्ष न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शन की घटनाओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचियों से कहा कि वे राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में जाएं और वही इस तरह की जांच समिति गठित कर सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने याचियों को राहत और जांच समिति के गठन के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य का संज्ञान लिया कि याचियों के आरोपों के प्रत्येक तथ्य को केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गलत बताया।

नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते प्रदर्शनकारी

दिल्ली में बवाल

नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंगलवार को कई मोटरसाइकिलें फूंक दी, पुलिस कर्मियों पर पथराव किए और बसों तथा एक पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभ्य समाज में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने बताया कि सीलमपुर में पुलिस के साथ हुई झड़पों में छिपी हुई भीड़ थी जो बढ़कर चार से पांच हजार लोगों तक पहुंच गई। हालांकि हालात काबू में हैं।

पुलिस की गोली नहीं

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जामिया विश्वविद्यालय के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई पर इलाके से कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें कोई जामिया का छात्र नहीं है।

विदेश में भी हलचल

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक सलाहकार ने कहा है कि अगर भारत में किसी भी बांग्लादेशी नागरिक के अवैध रूप से रहने का सबूत दिया जाता है तो उनका देश उसे वापस बुलाएगा। देश के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन का विरोध ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, येल एवं एमआईटी समेत दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं ने भी किया।

मोदी: पाकिस्तानियों को नागरिकता देगी कांग्रेस ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करने की चुनौती दी कि वे सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करके और तीन तलाक कानून को समाप्त करके दिखाए। झारखंड की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों से लोकतांत्रिक तरीकों से अपने विषय उठाने की अपील की। *एजेंसियां*

कानून वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। मुंबई में इंडिया इकॉनमिक कॉन्क्लेव में शाह ने कहा कि उनकी पार्टी और सरकार चट्टान की तरह इस कानून के पीछे खड़े हैं। शाह ने कहा कि इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर नहीं बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल हैं। शाह ने कहा कि कानून में कुछ भी अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें।

लोगों की आवाज दबा रही है सरकार : सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोगों की आवाज दबा रही है और ऐसे कानून ला रही है जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। सोनिया गांधी संशोधित नागरिकता कानून और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने गए विपक्षी शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि स्थिति काफी गंभीर है। विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने जिस ढंग से कार्रवाई की उससे वे काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जामिया मिल्लिया इस्लामिया में महिला हॉस्टल में भी घुस गई और छात्रों की निर्ममता से पिटाई की।

पाक प्रस्ताव भ्रम फैलाने वाला: विदेश मंत्रालय

भारत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि यह पड़ोसी देश द्वारा अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार एवं उत्पीड़न से ध्यान हटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। मंत्रालय ने कहा कि इस कानून में किसी भारतीय की नागरिकता उसके धर्म के आधार पर छीने जाने का प्रावधान नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली ने स्वयं अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानून पारित किए हैं और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं।'

मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा

- मुशर्रफ एकमात्र ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें मिली है मौत की सजा
- पाक सेना ने कहा मुशर्रफ नहीं हो सकते देशद्रोही
- मुशर्रफ की पार्टी फैसले के खिलाफ करेगी अपील
- मुशर्रफ ने 1999 में किया था तख्तापलट

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सैन्य प्रमुख को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा सुनाई गई है। देशद्रोह के मामले में उन्हें दोषी ठहराना उस देश के लिए महत्त्वपूर्ण क्षण है जहां स्वतंत्र इतिहास में अधिकतर समय तक शक्तिशाली सेना काबिज रही है।

मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 1999 में तख्ता पलट में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। वह 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे।

अदालत के दो न्यायाधीशों ने मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य न्यायाधीश की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटों में सुनाए जाएंगे। फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत ने अभियोजकों की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें फैसले को टालने की मांग की गई थी। पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से वापस नहीं लौटे हैं। विशेष अदालत में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम शामिल हैं। अदालत ने 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देशद्रोह कानून, 1973 के मुताबिक देशद्रोह के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर उन्होंने देशद्रोह के मामले को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा, 'मैंने दस वर्षों तक अपने देश की सेवा की है। यह देशद्रोह का मामला है जिसमें मेरी बात नहीं सुनी गई और मुझे प्रताड़ित किया गया।'

अब उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय में फैसले को चुनौती देगी। अगर शीर्ष अदालत विशेष न्यायालय के फैसले को बरकरार रखती है तो अनुच्छेद 45 के तहत राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह मौत की सजा प्राप्त व्यक्ति को माफी दें। विशेष अदालत का यह आदेश इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व के एक आदेश के बावजूद आया है जिसमें उसे फैसला देने से रोका गया था। उच्च न्यायालय का आदेश 27 नवंबर को आया। मुशर्रफ ने लाहौर उच्च न्यायालय से विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर तब तक रोक लगाने को कहा था जब तक कि उनकी पूर्व याचिका पर उच्च न्यायालय फैसला नहीं ले लेता। *भाषा*

किसान कर्जमाफी से मध्य प्रदेश में बैंक के फंसे कर्ज में इजाफा

संजीव मुखर्जी

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से हजारों की संख्या में किसान सहकारी समितियों एवं उर्वरक दुकानों के आगे कतारों में खड़े दिख जाते हैं। ये किसान यूरिया लेने के लिए तब जद्दोजहद कर रहे हैं जब गेहूं बुआई का समय चरम पर पहुंच चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अधिक समय तक सक्रिय रहने से गेहूं की बुआई के लिए काफी कम समय रह गया है, जिस वजह से राज्य में यूरिया की मांग अचानक बढ़ गई है। गेहूं के किसान अमूमन यूरिया का भंडारण नहीं करते हैं। गेहूं की अच्छी फसल के लिए दो बार यूरिया डालने की जरूरत होती है। सबसे पहले बुआई के एक पखवाड़े के भीतर और दूसरी बार बुआई के करीब डेढ़ महीने बाद यूरिया छिड़काव की आवश्यकता होती है।

दीपक शर्मा

- नीति निर्धारक और विशेषज्ञ कई बार कर चुके हैं कृषि ऋण माफी योजना की आलोचना। उनका मानना है कि इससे किसानों को लाभ के बजाय लंबी अवधि में नुकसान अधिक होता है
- राज्य में दिसंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच बैंकों के एनपीए में हुआ 2,949 करोड़ रुपये का इजाफा

ऋण माफी : नफा या नुकसान का सौदा?

अब अगर मध्य प्रदेश में किसी किसान को अपने खेत में कल यूरिया का छिड़काव करना है तो ज्यादातर मामलों में वह नजदीकी सहकारी समिति या सरकारी दुकान जाएगा और नकद भुगतान के बाद एक दिन पहले यूरिया ले पाएगा। इसकी वजह यह है कि ये किसान ऋण माफी योजना के बाद अब ऋण पर बीज एवं उर्वरक खरीदने के पात्र नहीं रह गए हैं। सरकारी माध्यमों से यूरिया उपलब्ध नहीं होने पर किसानों के लिए निजी डीलरों से ऊंचे दाम पर इस उर्वरक की खरीद के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है।

आखिर मध्य प्रदेश के कई किसानों के सामने यह नौबत पेश क्यों आई है? कुछ का मानना है कि स्थानीय स्तर पर कुप्रबंधन और किसान ऋण माफी योजना यूरिया संकट के लिए मोटे तौर पर जिम्मेदार है। उनका कहना है कि ऋण माफी योजना के कारण कई किसानों ने छोटी अवधि के अपने ऋण खातों का नवीकरण नहीं किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वे नए बीज एवं उर्वरक ऋण लेकर खरीदने के योग्य नहीं रह गए हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये आरोप सही साबित हुए तो कर्ज माफी योजना पर यह एक और काला धब्बा साबित हो सकता है। नीति निर्धारक और विशेषज्ञ कई बार कृषि ऋण माफी योजना की आलोचना कर चुके हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को लाभ के बजाय दीर्घ अवधि में नुकसान अधिक होता है। ज्यादातर विशेषज्ञों ने ऋण माफी को अस्थायी समाधान बताया है। दरअसल किसानों की खस्ता हालत की वजह कृषि क्षेत्र में निवेश का अभाव, उपज की कम कीमत, भंडारण क्षमता का अभाव और कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार के उपायों की कमी है।

बैंक एनपीए में दिखती बढ़ोतरी

ऋण माफी से उन राज्यों में बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) भी बढ़ी हैं, जिन राज्यों में इसकी घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि ऋण माफी योजना 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' से राज्य में बैंकों के एनपीए में इजाफा हुआ है। राज्य में दिसंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच बैंकों के एनपीए में 2,949 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। एसएलबीसी रिपोर्ट में कहा गया है, 'इनके अलावा बैंकों का बढ़ता बकाया भी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। इससे वित्तीय संस्थानों को नए ऋण देने में मुश्किलें पेश आ रही हैं।' रिपोर्ट में कहा गया है कि कई स्थानों पर किसान ऋण माफी का प्रमाण पत्र (रिसीट) मिलने का इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्राप्ति के बाद ही वे अपने खाते का परिचालन शुरू करेंगे। जिन खातों का नवीकरण नहीं हुआ है, उनके लिए बीज एवं उर्वरक ऋण पर उपलब्ध नहीं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी बैंकों का बकाया कृषि ऋण दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच सबसे अधिक 13.52 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है। ऋण माफी योजना के निपटान के लिए सहकारी बैंक सबसे पसंदीदा माध्यम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस रुझान से यह माना जा सकता है कि कृषि ऋण माफी योजना से ऋण आवंटन एवं पुनर्भुगतान ढांचा अस्त-व्यस्त हो जाता है। सभी योग्य किसानों को समय पर लाभ देकर इसका असर कम किया जा सकता है।'

ऋण माफी पर धीमी गति से बढ़ रहे राज्य

मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ ने किसान ऋण माफी योजना का ऐलान किया था। एसएलबीसी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2018 और 2019 के बीच कृषि ऋण आवंटन में लगभग 315 करोड़ रुपये कमी दर्ज की गई। एक बार फिर कृषि ऋण माफी योजना इसकी एक वजह हो सकती है। इन दोनों राज्यों के साथ राजस्थान ने भी किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। हालांकि वहां के आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हालिया आंतरिक कार्यशील समूह की रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों राज्यों ने 2019-19 से अगले कुछ वर्षों के लिए संयुक्त रूप से 60,600 करोड़ रुपये के किसान ऋण माफ करने की घोषणा की थी। 2019-20 तक इन तीनों राज्यों के बजट में लगभग आधी (28,300 करोड़ रुपये या 47 प्रतिशत) रकम का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश में पहले दो बजट 2018-19 और 2019-20 में 36,500 करोड़ रुपये घोषित ऋण माफी में केवल करीब 36 प्रतिशत का ही प्रावधान हुआ है, जबकि राजस्थान में घोषित 18,000 करोड़ रुपये कर्ज माफी का 100 प्रतिशत तक प्रावधान हो चुका है। वास्तव में 2014-15 से अब तक भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कुल 10 राज्य 2,36,460 करोड़ रुपये मूल्य की कर्ज माफी की घोषणा कर चुके हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इनमें 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में इन राज्यों के बजट में 1,49,800 करोड़ रुपये के प्रावधान किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर राज्यों ने अपने खजाने पर बोझ कम करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना के लिए प्रावधान चरणबद्ध तरीके से किए हैं।

किंगमेकर बनने की ख्वाहिशों की उड़ान

आजसू के प्रमुख सुदेश महतो उद्धव ठाकरे होने की कामना कर सकते हैं लेकिन झारखंड में नहीं है कोई शरद पवार

राधिका रामशेषन

कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अपने पुराने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बगैर सुदेश महतो का झारखंड के चुनावी दंगल में कूदना बेवकूफी भरा या बेहद साहसिक कदम हो सकता है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के प्रमुख सुदेश महतो को 2014 के रांची लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। 2018 के एक उपचुनाव में वह रांची जिले के एक पूर्व शहर सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के एक उम्मीदवार से हार गए। उनकी पार्टी आजसू के करीबी समर्थक भले ही इस बात की पुष्टि न करें लेकिन रांची की सियासी चर्चा में यह बात उभर कर आती है कि महतो ने उसी दिन भाजपा का साथ छोड़ने का फैसला किया था जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजे निकले थे।

इन राज्यों के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं रहे भले ही पार्टी इन राज्यों में अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी। 2014 के बाद से सत्ता समर्थक रुझान की सवारी करने के बाद महतो को भाजपा असुरक्षित लगने लगी खासतौर पर हरियाणा में छोटी पार्टी के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और मुंबई में सरकार बनाने के लिए ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा जिस पर सवाल भी खड़े हुए।

रांची में एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, 'उनकी महत्वकांक्षा उभर रही थी। वह खुद को दूसरे उद्धव ठाकरे समझ रहे थे हालांकि झारखंड दूसरा महाराष्ट्र नहीं हैं और यहां कोई शरद पवार भी नहीं हैं।' भाजपा ने राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों की पेशकश महतो से की जो 2014 की सीटों के मुकाबले तीन सीटें ज्यादा थीं। उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि 2019 में किंगमेकर या किंग बनना एक बेहतर रणनीति थी। हालांकि उनकी सबसे पहली चुनौती सिल्ली से सीमा देवी को हराना होगा बाकी चीजें इसके दायरे के बाहर हैं।

महत्वाकांक्षा भी नए कलेवर में सामने आ रही है मसलन, 'अबकी बार, गांव की सरकार' से महतो का एजेंडा नहीं छिप सकता है। जब वह अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट से चलते हैं तब उनके साथ आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत होते हैं और उनके समर्थक जोरदार तरीके से नारा लगाते हैं, 'झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुदेश महतो जैसा हो।' छह महीने पहले 45 साल के महतो ने आईटी और सोशल मीडिया को गंभीरता से लेना शुरू किया और उन्होंने दमदार तरीके से फेसबुक, ट्विटर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, कई गांवों में कॉल सेंटर स्थापित करने के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनकी रैलियों और रोड शो का प्रसारण सोशल मीडिया पर मौजूद उनके तकनीकी समर्थक कर देते हैं।

महतो अपने आत्मविश्वास के लिए तीन वजहों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका दावा है, 'मैं साल 2000 से ही सरकार में मंत्री रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह के घोटाले का दाग नहीं है।' हालांकि हिंडाल्को का भूत महतो को डरा रहा है। अप्रैल 2019 में सिल्ली के लगम गांव में स्वर्णरेखा नदी के किनारे मुरी रिफाइनरी संयंत्र की दीवारों में दरार दिखने लगी। सिल्ली में लाल रंग का विषाक्त कचरा निकलने लगा जिससे एक मजदूर की मौत हो गई और करीब आधे दर्जन लोग घायल हो गए। इस संयंत्र का परिचालन बंद हो गया जिसकी वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई। महतो का ताल्लुक लगम से है और उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगर वे उन्हें वोट देते हैं तो वह रिफाइनरी को फिर से शुरू करेंगे और उन्हें उनकी नौकरियां वापस मिल जाएंगी।

इसमें कोई शक नहीं कि महतो ने आजसू संगठन को मजबूती देने के लिए देसी तर्ज पर 'चूल्हा प्रमुख' बनाने पर जोर दिया है जो संगठन की संरचना की मुख्य इकाई है। भाजपा के पन्ना प्रमुख के मुकाबले 'चूल्हा प्रमुख' की भूमिका बूथ मैनेजमेंट तक है। ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि गांवों से लाए गए पुरुष और महिलाएं हैं। महतो 'दादा' के नाम से जाने जाते हैं और वह पहली पीढ़ी के नेता हैं जो कुर्ता पायजामा की परंपरागत छवि को धता बताते हुए जीन्स, कैजुअल शर्ट और स्पोर्ट्स शू पहनते हैं।

फिटनेस को लेकर उनमें गजब का जुनून है और वह चुनावी अभियान के बावजूद जॉगिंग करते हैं। वह फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और उन्होंने सिल्ला में झारखंड के स्वतंत्रा सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर एक तीरंदाजी अकादमी खोला है। आजसू की स्थापना 22 जून 1986 में हुई थी और इस पार्टी ने एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की। महतो ने ही बिरसा मुंडा और कोयलांचल के सामाजिक कार्यकर्ता बिपिन बिहारी महतो की मूर्ति बनाने पर जोर दिया था। महतो अपना पहला चुनाव साल 2000 में लड़े और जीत गए। इसी साल झारखंड राज्य बना था। महज 25 साल की उम्र में वह भाजपा के नेतृत्व वाली बाबुलाल मरांडी की सरकार में एक मंत्री बने और 2009 में गठबंधन की सरकार में वह उप मुख्यमंत्री बने। एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि वह कभी सत्ता से दूर नहीं रहे।

आखिर अब क्या होगा? अगर राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो क्या वह भाजपा खेमे में वापस आएंगे या फिर नए सहयोगी की तलाश करेंगे? भाजपा के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह महतो का पार्टी में स्वागत करेंगे। अब भविष्य में क्या होगा, यह कौन जानता है?